RNI No. 58061/93 | वर्ष - 21 | अंक - 326 | पृष्ठ - 8 | रु. 5/- | बेंगलूरु » शुक्रवार » 26-06-2026 | www.dakshinbharat.com | Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 संविधान की रक्षा के बहाने 'लोकतंत्र-विरोधी गतिविधियां' करते हैं कांग्रेस नेता : नड्डा

6 टूटते रिश्ते, बुझती संवेदनाएँ और बढ़ते अपराध

7 'आपातकाल भारत के संविधान पर सीधा हमला था': कंगना रनौत

फर्स्ट टेक

सरकार ने बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। पांच से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दिए जाने वाले इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनके ''अद्वितीय धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य भावना'' का सम्मान करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह पुरस्कार 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

चीन, बांग्लादेश तीस्ता नदी प्रबंधन पर सहयोग मजबूत करने को सहमत

बीजिंग/भाषा। बांग्लादेश और चीन बृहस्पतिवार को तीस्ता और अन्य नदियों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के प्रधानमंत्री ली क्रिंग के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंध मजबूत करने के लिए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील है। ऐसे में तीस्ता जल प्रबंधन को लेकर चीन के साथ सहयोग का असर भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर पड़ सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने संवाददाताओं को बताया कि अभी बीजिंग में मौजूद रहमान और चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग के बीच हुई बैठक में नदियों के जल प्रबंधन में सहयोग पर सहमति बनी।

ब्रिक्स देशों में ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा सहयोग मजबूत करने पर सहमति

नई दिल्ली/भाषा। ब्रिक्स देशों ने बृहस्पतिवार को ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, नवोन्मेष, मजबूत बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर आम सहमति व्यक्त की। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत गुरुग्राम में आयोजित '11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक' में सदस्य देशों के मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा मार्गों का सम्मान करने के महत्व को दोहराया। बैठक का समापन 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के संयुक्त घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ।

सूर्यास्त 26-06-2026 6:49 बजे | सूर्योदय 27-06-2026 5:56 बजे

BSE	NSE
77,100.47 (+109.25)	24,056.00 (+34.35)

सोना	चांदी
14,861 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	222,580 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

थूक फजीती

दल बाँट रहे महापुरुषों को,
अपनी खिसियाहट के कारण।
मृतकों को अपमानित करके,
लड़ रहे सियासत का वे रण।
कुछ शर्म करो दल धृतराष्ट्रों,
तक रहा वक्त तुमको प्रति क्षण।
इस थूक-फजीती को लख-सुन,
आक्रोशित है अब जन मन गण।।

ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि

स्वदेशी रक्षा क्षमताएं रणनीतिक प्रभावशीलता के लिए अहम हैं : मुर्मू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि आत्मनिर्भर देश आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अधिक सक्षम होता है और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं किसी देश की अभियानगत तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती हैं।

यहां राष्ट्रपति भवन में सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि वर्तमान समय में, जब दुनिया विभिन्न संघर्षों और भू-राजनीतिक तनावों का सामना कर रही है, आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट की परिस्थितियों में अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में अधिक सक्षम होता है।

राष्ट्रपति ने कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी भी राष्ट्र की अभियानगत तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता को सशक्त बनाने में कितने महत्वपूर्ण होते हैं।''

'ऑपरेशन सिंदूर' देश की रक्षा सेनाओं द्वारा चलाया गया था, जिसमें सात से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।

मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, ''इस स्थिति में, सतत विकास अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गया है।''

राष्ट्रपति ने उनसे हरित तकनीकों को अपनाने, ऊर्जा और पानी की बचत करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''जो अवसंरचना मजबूत, कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होगी, वह न केवल आज की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हितों की भी रक्षा करेगी।''

कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध के सभी 33 'स्पिलवे गेट' खोले गए

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने किया उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोप्पल/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को यहां तुंगभद्रा बांध पर नये 33 'स्पिलवे गेट' का उद्घाटन किया।

कोप्पल जिले के मुनीराबाद तालुका स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में तीनों राज्यों के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। आयोजन जल संसाधन विभाग और तुंगभद्रा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यक्रम से पहले नेताओं ने बांध क्षेत्र का दौरा किया, वहां विशेष पूजा-अर्चना की और बांध के 17, 18, 19 तथा 20 नंबर के गेटों का उद्घाटन किया।

'परिसंपत्तियों के निर्माण में कर्ज की राशि का उपयोग करें राज्य'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कांचीपुरम/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधन सीमित होने की स्थिति में नकद वितरण जैसे राजस्व व्यय पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय अपने कर्ज के पैसे का इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल जैसे दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय में करना चाहिए।

संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और अगले 50 से 60 वर्षों तक रोजगार के अवसर पैदा करता है। उन्होंने कहा, कर्ज लेना कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उस कर्ज के पैसे का क्या करते हैं, यह मायने रखता है। क्या आप संपत्तियां बना रहे हैं? क्या उससे शिक्षा, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है? ध्यान इस पर होना चाहिए।'' वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का तीन प्रतिशत तक कर्ज लेने की अनुमति है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के दो दिवसीय दौरे पर आईं सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कांचीपुरम स्थित श्री उपनिषद ब्रह्मेंद्र मठ के महा कुंभाभिषेक समारोह में भाग लिया। बाद में वह पुडुचेरी जाएंगी, जहां केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय परिसर में स्थित औपनिवेशिक काल के एक पुनर्निर्मित 'लाइटहाउस' का उद्घाटन करेंगी।

अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब युवाओं को आतंकवादी कह रही है : राहुल गांधी

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि ''अहंकार में डूबी'' मोदी सरकार अब निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग करने वाले युवाओं को आतंकवादी बता रही है। उन्होंने कहा कि प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। प्रधान ने हाल ही में नीट-यूजी पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बीच 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के प्रदर्शनकारियों को ''दहशतगर्दों की बी-टीम'' कहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''ज़रा सोचिए, कि जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया।

राम मंदिर 'दान गबन' मामले में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

अयोध्या (उप्र)/भाषा। अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित वित्तीय अनिमियतताओं से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

इससे दो दिन पहले मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

सूत्रों के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड़यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के

वेनेजुएला में दो तीव्र भूकंप से 164 लोगों की मौत, 1000 घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

काराकस (वेनेजुएला)/एपी। वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंप से मची तबाही के बीच बृहस्पतिवार को राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया। बुधवार शाम लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आए जिससे कम से कम 164 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1000 लोग घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से प्रांतों में भारी नुकसान हुआ और कई इमारतें ढह गईं। बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं।

भूकंप से देश का प्रमुख हवाईअड्डा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण विमानों का परिचालन रोक दिया गया है। भूकंप का असर पड़ोसी देशों तक महसूस किया गया, और ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में भी कई इमारतों को खाली कराया गया।

बृहस्पतिवार को टेलीविजन पर दिखाए गए दृश्यों में बचावकर्मी विभिन्न उपकरणों की मदद से मलबे के ढेर के बीच रास्ता बनाते हुए दिखे, जहां कभी इमारतें हुआ करती थीं। राजधानी काराकस में घबराए हुए लोग सड़कों पर निकल आए और भूकंप के बाद कई लोग मलबे के बीच लापता लोगों को ढूंढते दिखे।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बृहस्पतिवार को कहा कि भूकंप में कम से कम 164 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं।

केंद्र गोवा के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बुनियादी परियोजनाओं के लिए निधि देने को तैयार : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मडगांव/भाषा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को आश्वासन दिया कि गोवा के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों जैसे स्कूल भवनों, चिकित्सा सुविधाओं, कौशल विकास और उद्यमिता योजनाओं के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपलब्ध केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है।

रीजीजू ने दक्षिण गोवा में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि वह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से चर्चा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का लाभ समुदायों तक पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि केंद्र की प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)' उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कमी को पूरा करने वाली धनराशि उपलब्ध कराती है, जहां अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है।

रीजीजू ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को पर्याप्त सहायता मिले तथा वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि गोवा ने उपलब्ध धनराशि का अधिक उपयोग नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जहां भी अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है, वहां हम विद्यालयों, स्कूल भवनों, चिकित्सा सुविधाओं, खेल स्टेडियम, पुस्तकालयों, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य जरूरतों के लिए योजनाओं को वित्त पोषित कर सकें।

तेल के दाम युद्ध से पहले के स्तर पर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत पश्चिम एशिया में तनाव शुरू होने से पूर्व के स्तर पर आ गयी है। इससे महंगाई का खतरा कम होने, आयात बिल घटने और सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चा तेल आयातक भारत के लिए स्थिति काफी अनुकूल हो गयी है।

वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत टूटकर लगभग 72-73 डॉलर प्रति बैरल, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। इससे उस भू-राजनीतिक जोखिम के कारण बढ़ी हुई कीमत का असर खत्म हो गया है, जिसके कारण इस साल की शुरुआत में तनाव बढ़ने पर दाम 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। दोनों मानक अब फरवरी के आखिर के स्तर के करीब आ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद बृहस्पतिवार को खुदरा ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाल ही में वैश्विक स्तर पर तेल के दाम में तेजी के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने अब तक पेट्रोल पंप पर कीमतें कम नहीं की हैं। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन खुदरा ईंधन विक्रेता अभी पेट्रोल पर अच्छा विपणन मार्जिन कमा रहे हैं। हालांकि, डीजल की बिक्री से अब भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लगभग ढाई महीने तक खुदरा कीमतें स्थिर रखी थीं और उसके बाद ही कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की थी। ईंधन कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में रोजाना होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर तय नहीं की जाती हैं, बल्कि आमतौर पर पिछले दो सप्ताह या महीने की औसत तेल कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं। इसके कारण, अगर अंतरराष्ट्रीय दरें कम बनी रहती हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में हाल की गिरावट का फायदा पेट्रोल पंप तक पहुंचने में समय लग सकता है।

अदाणी समूह देशभर में 'एयरपोर्ट सिटी' परियोजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अदाणी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड (एएसीएल) ने पांच राज्यों के छह हवाई अड्डों पर 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 'एयरपोर्ट सिटी' विकसित करने के लिए पहले चरण में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की योजना की घोषणा की है।

भारत की सबसे बड़ी निजी हवाई अड्डा संचालक अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एएसीएल ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस परियोजना के तहत मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी हवाई अड्डों के आसपास लगभग 2.2 करोड़ वर्ग फुट मिश्रित उपयोग वाली बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, कुल निवेश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा मुंबई और नवी मुंबई में किया जाएगा, जहां उसके पास करीब 440 एकड़ भूमि है। इन परियोजनाओं के तहत होटल, कार्यालय, खुदरा परिसर, मनोरंजन सुविधाएं, सम्मेलन केंद्र और अन्य जीवनशैली संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किये जाएंगे, जिन्हें महानगर और शहरी परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

एएएचएल के निदेशक जीत अदाणी ने कहा, हवाई अड्डों के पास कहीं अधिक आर्थिक मूल्य सृजित करने का अवसर है। हमारा उद्देश्य प्रमुख विमानन केंद्रों के आसपास निवेश, रोजगार और शहरी विकास को बढ़ावा देना है। यह मॉडल सिंगापुर चांगी, दुबई इंटरनेशनल, एम्स्टर्डम शिफोल और सियोल के इंचियोन जैसे वैश्विक स्तर पर सफल हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य केवल यात्री यातायात पर निर्भर न रहकर एक एकीकृत व्यापार और पर्यटन परिवेश तैयार करना है।

कंपनी ने बताया कि 'एयरपोर्ट सिटी' की इन सभी परियोजनाओं को 'यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल' से 'लीड गोल्ड' पूर्व-प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो इसके पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को दर्शाता है।

टोरेंट पावर ने नाभा पावर का 3,632 करोड़ रुपए में अधिग्रहण पूरा किया

नई दिल्ली/भाषा। टोरेंट पावर ने एलएंडटी पावर डेवलपमेंट लि. से नाभा पावर लिमिटेड (एनपीएल) में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी 3,632.35 करोड़ रुपए में खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने शेयर बाजार को एनपीएल में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी और परिवर्तनीय संपत्ति खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता करने और इस अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी मिलने के बारे में जानकारी दी थी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने एलएंडटी पावर डेवलपमेंट लि. से एनपीएल के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय संपत्ति कुल 3,632.35 करोड़ रुपए में खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। टोरेंट समूह की इकाई टोरेंट पावर बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिजली पारेषण केबल के विनिर्माण और आपूर्ति के कारोबार में जुड़ी हुई है।

सरकार लोगों की नागरिकता छीनने की जमीन तैयार कर रही : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार पासपोर्ट के नाम पर अब लोगों की नागरिकता छीनने की जमीन तैयार कर रही है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह दावा भी किया कि उन भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा जो सरकार से वैचारिक और राजनीतिक असहमति रखते हैं।

दरअसल, सरकार के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है और मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में इस दस्तावेज़ को लेकर कोई नया फ़ैसला नहीं लिया है। पासपोर्ट को यात्रा दस्तावेज बताने और नागरिकता का सबूत नहीं होने संबंधी विदेश मंत्रालय के बयान पर मीडिया में आई खबरों को लेकर सूत्रों ने कहा कि यह कल तय नहीं किया गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''यह सरकार आम नागरिकों के बीच भय का माहौल पैदा करने में माहिर है। यह कहकर कि पासपोर्ट भी किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वह उन भारतीय नागरिकों के नागरिक अधिकारों को मनमाने ढंग से नकारने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे उसकी वैचारिक या राजनीतिक असहमति है।''

उन्होंने कहा, ''हम भली-भांति जानते हैं कि अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए कुछ समुदायों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के गुप्त प्रयास किए जा रहे हैं।'' कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वह दिन दूर नहीं जब यह फासीवादी शासन राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर लोगों की नागरिकता भी छीन लेगा, भले ही उनके पास भारतीय होने का प्रमाण देने वाला पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज क्यों न हो।

कांग्रेस ने अलग-अलग शहरों से उठाई प्रधान के इस्तीफे की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में कथित धांधली के विषय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए बृहस्पतिवार को देश के 28 शहरों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।

पार्टी के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत 28 नेताओं ने 28 शहरों में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार ''बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ की जवाबदेही'' से नहीं बच सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट के माध्यम से सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ''अहंकार में डूबी'' मोदी सरकार अब निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग करने वाले युवाओं को आतंकवादी बता रही है। राहुल ने कहा कि प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। प्रधान ने हाल में नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक और अन्य परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शनकारियों को ''दहशतगर्दों की बी-टीम'' कहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने पोस्ट किया, ''सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं।''

आपातकाल भारत के इतिहास का 'काला अध्याय' : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भारत के इतिहास का 'काला अध्याय' करार देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस 'संविधान की आत्मा को कुचलने' की कोशिश कर रही है।

शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मोदी सरकार द्वारा 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का उद्देश्य इस काले अध्याय को राष्ट्र की स्मृति में जीवित रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान पर ऐसा आघात कभी दोबारा न कर सके।'' उन्होंने कहा, '' 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के सत्ता के अहंकार तथा लालच ने संविधान की आत्मा, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने का प्रयास किया था।'' शाह ने कहा,''...संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर लोकतंत्र के उन सभी सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की।

देर रात किसी पुरुष से महिला का फोन पर बात करना उसके चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं: अदालत

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि महज इसलिए कि कोई महिला देर रात फोन पर किसी पुरुष से बात करती है, उसके चरित्र पर सवाल उठाने का कारण नहीं हो सकता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता ने एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

व्यक्ति ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें घरेलू हिंसा के एक लंबित मामले में उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के 'कॉल डिटेल रिकॉर्ड' (सीडीआर) को सुरक्षित रखने की उसकी मांग को खारिज कर दिया गया था।

अदालत ने 2 जून के एक आदेश में कहा, ''मेरी राय में, ...किसी व्यक्ति से बात करने मात्र से ही महिला के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, जब तक कि यह आरोप न लगाया गया हो कि महिला का उस व्यक्ति के साथ कोई गैर-कानूनी या व्यभिचारपूर्ण संबंध है।''

सिख गुरुओं का अनादर करने का किसी को अधिकार नहीं, इस्तीफा दें मान: प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक विवादित वीडियो के सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की।

प्रधान ने कहा कि किसी को भी सिख गुरुओं का अनादर करने का अधिकार नहीं है। यह आस्था का विषय है। हमारे मन में गुरुओं के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा है। किसी को भी उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका अपमान किया है। उन्हें जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, उनका उन्हें सामना करना होगा। नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधान ने मान से जुड़े विवादित वीडियो के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही। प्रधान, आपातकाल लागू किए जाने के 51 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है जिसके संबंध में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने 15 जून को मान के खिलाफ एक आदेश जारी किया था। यह मामला इस वर्ष जनवरी में शुरू हुआ था जब भगवंत मान को 'गुरु की गोलक' (गुरुद्वारे के दान पात्र) पर कथित टिप्पणी करने और एक कथित वीडियो क्लिप में सिख गुरुओं व मारे गए उग्रवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अकाल तख्त ने तलब किया था।

एसआईटी सिर्फ दिखावा है, इसे ताकतवर लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है: अरविंद केजरीवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया और इसे लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास बताया।

अयोध्या जाते समय लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एसआईटी का उद्देश्य श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित अनियमितता के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के बजाय प्रभावशाली लोगों को बचाना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का हवाई अड्डे पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि वह राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और संतों से मिलने के लिए अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, मीडिया और सोशल मीडिया पर आयी खबरों से पता चलता है कि श्रद्धालुओं द्वारा गहरी भक्ति के साथ भगवान को चढ़ाए गए हीरे और कीमती पत्थर कथित तौर पर चोरी हो गए हैं, 200 करोड़ रुपए तक की नकदी कथित तौर पर चोरी हो गई है और यहां तक कि किसी द्वारा दान की गई 200 किलोग्राम चांदी भी कथित तौर पर चोरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इसने श्रद्धालुओं की भावनाओं को बहुत आहत किया है। केजरीवाल ने कहा, मैं बहुत व्यथित हूं। मेरे जैसे करोड़ों-करोड़ों लोग हैं जो बहुत व्यथित हैं। इसलिए मैं अयोध्या जा रहा हूं। कल मैं राम मंदिर जाऊंगा और भगवान राम की पूजा करूंगा और हनुमानगढ़ी भी जाऊंगा। आप नेता ने कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि करोड़ों रुपए के दान से जुड़े आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

आईआरएफसी में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार ने जुटाए करीब 2,100 करोड़ रुपए

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) में हिस्सेदारी बिक्री के जरिये लगभग 2,100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि आईआरएफसी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को खुदरा निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा, संस्थागत निवेशकों के साथ मिलाकर दो कारोबारी दिनों में अल्पांश शेयरधारकों को 22.88 करोड़ शेयर बेचे गए, जिससे अनुमानित 2,084 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हम सभी निवेशकों को उनकी भागीदारी और हम पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देते हैं। सरकार ने बुधवार को 'ग्रीन शू' विकल्प का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इससे रेल मंत्रालय के इस सार्वजनिक उपक्रम में दो प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की जा सकी। दीपम ने ओएफएस के लिए 91 रुपए प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य तय किया था, जो मंगलवार को बीएसई पर आईआरएफसी के शेयर के बंद भाव की तुलना में 7.8 प्रतिशत कम था। बीएसई पर बृहस्पतिवार को आईआरएफसी का शेयर 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 91.78 रुपए पर बंद हुआ।

अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही को एनसीएलटी में चुनौती दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उद्योगपति अनिल अंबानी ने अपने खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी है। यह कार्यवाही भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दायर याचिका के आधार पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुरू की थी।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 11 जून को भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही की अपील की गई थी। यह मामला उनकी समूह कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा ऋण के भुगतान में चूक से जुड़ा है। अनिल अंबानी इन ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटर थे। अंबानी की अपील पर न्यायमूर्ति मो. फैज़ आलम खान और बरुण मित्रा की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई हुई, लेकिन उनके अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले को आगे के लिए टाल दिया गया। एनसीएलएटी के 24 जून, 2026 के आदेश में कहा गया, ''अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को 10 जुलाई, 2026 को न्यायालय के सामने सूचीबद्ध किया जाए।'' भारतीय स्टेट बैंक ने दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 95 के तहत आवेदन दायर किया, जो लेनदारों को कर्जदारों और व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है। बैंक ने दावा किया एक मार्च, 2019 तक लगभग 853.25 करोड़ रुपए का ऋण बकाया था, जो अंबानी द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ा है।

विवादित वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं : भगवंत मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। एक विवादित वीडियो को लेकर विपक्षी दलों की बढ़ती आलोचनाओं के बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को दोहराया कि वह उस वीडियो में नहीं थे और दावा किया कि आपत्तिजनक क्लिप में दिख रहे व्यक्ति ने उनके चेहरे जैसा दिखने वाला मास्क पहना हुआ था।

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विपक्षी दलों कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर धार्मिक मुद्दों को लेकर उन्हें बदनाम करने के साठगांठ करने का आरोप लगाया। मान ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक वीडियो दिखाया और दावा किया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने जो मास्क पहना था, वह उनके चेहरे जैसा था। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे उस व्यक्ति की गर्दन पर वह निशान भी नहीं था जो उनके है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उस कथित वीडियो में वह नहीं थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कनाडा में रहने वाला एक व्यक्ति यह मास्क लेकर आया था। उसकी पहचान उन्होंने जगमन समरा के रूप में की और उसे ''ब्लैकमेलर'' बताया। मान ने एक और वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि समरा उस नकाब को पकड़े हुए था, जो उनके चेहरे जैसा दिखता है। उन्होंने कहा, ''इस नकाब को हाथ में पकड़े हुए इस ब्लैकमेलर ने इसे किसी और व्यक्ति को पहनाकर वीडियो बनाया।''

मान ने दावा किया कि यह वीडियो कनाडा के एक होटल के कमरे में बनाया गया था। मुख्यमंत्री कहा कि वह नवंबर 2016 के बाद से कनाडा नहीं गए हैं। मान ने कहा, ''मैं कहता आ रहा हूं कि उस वीडियो में मैं नहीं हूं, क्योंकि वीडियो क्लिप में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई और शारीरिक बनावट मुझसे मेल नहीं खाती है।'' मान ने कहा कि वह आने वाले दिनों में बताएंगे कि वीडियो का निर्माता और निर्देशक कौन है। वीडियो से जुड़ा विवाद बढ़ने पर, बुधवार को मान ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे धार्मिक मुद्दों के जरिए उन्हें बदनाम करने के लिए एकजुट हो गई हैं। उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्हें दोषमुक्त करने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट जाली थी।

स्वदेशी अवाक्स 'नेत्र' को परिचालन की अंतिम मंजूरी मिली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारत के स्वदेशी 'एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली' (अवाक्स) 'नेत्र' को बृहस्पतिवार को अंतिम परिचालन मंजूरी दे दी गई, जिससे इसके भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। वायुसेना के उपाध्यक्ष एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने यहां स्थित 'सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स' (सीएबीएस) में आयोजित एक समारोह में 'नेत्र' प्रणाली को औपचारिक रूप से अंतिम परिचालन स्वीकृति (एफओसी) प्रदान किए जाने की घोषणा की। समारोह के दौरान स्वदेशी 'नेत्र' प्रणाली और उससे संबंधित एफओसी प्रमाणपत्र का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर एयर मार्शल भारती ने कहा, नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन स्वीकृति (एफओसी) प्रदान करने की घोषणा करना वास्तव में गर्व का क्षण है। यह केवल एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की परिणति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भारतीय वायुसेना और वैज्ञानिक समुदाय के बीच अद्वितीय साझेदारी का उत्सव भी है। उन्होंने कहा कि नेत्र प्रणाली की यात्रा असाधारण रही है, हालांकि किसी भी नयी प्रणाली की तरह इसमें कई चुनौतियां भी सामने आईं। भारती ने कहा, हमें अत्यधिक धैर्य और दृढ़ता का परिचय देना पड़ा और सभी संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बीच सहयोग सुनिश्चित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत से ही वायुसेना केवल उत्पाद की आपूर्ति का इंतजार करने वाला उपभोक्ता नहीं था, बल्कि उसने रूपरेखा तैयार करने, विकास, एकीकरण, परीक्षण और परिचालन में प्रक्रिया भूमिका निभाई। एक वीडियो संदेश में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी) एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में 'नेत्र' प्रणाली की पूर्ण परिचालन क्षमता हासिल करने का राष्ट्रीय लक्ष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अवाक्स नेत्र भारत द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक हवाई निगरानी एवं कमान एवं नियंत्रण प्रणाली है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की सीएबीएस प्रयोगशाला में बनाया गया है। यह प्रणाली लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में सक्षम है।

'नेत्रा' वास्तविक समय में वायुसेना के लड़ाकू विमानों और जमीनी नियंत्रण कक्ष को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है, जिससे युद्ध के दौरान त्वरित और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है।

कर्नाटक का आबकारी विभाग रिश्वतखोरी के लिए एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा : ईडी

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में आबकारी विभाग रिश्वत वसूलने के लिए एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। ईडी ने दावा किया कि एजेंसी ने आबकारी अधिकारी वाई. डी. मंजूनाथ के पास से 13 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। मंजूनाथ, कर्नाटक सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सतीश जारकीहोली के संबंधी हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में यह भी दावा किया कि ईडी ने विभाग में धन शोधन के एक अनूठे तरीके के बारे में भी पता लगाया है जिसमें अधिकांश अधिकारियों ने अपने परिवार के सदस्यों या परिवार के नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर शराब के लाइसेंस प्राप्त कर रखे हैं और अवैध रूप से शराब का कारोबार चला रहे हैं। ईडी ने बुधवार को राज्य के आबकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार और विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के संबंध में बेंगलूरु, मैसूरु और बेलगावी स्थित 14 परिसरों पर छापेमारी की।

एजेंसी ने बताया कि जिन मुख्य लोगों के घरों पर छापे मारे गए, उनमें आबकारी अधिकारी वाई. डी. मंजूनाथ, जगदीश नायक और के. एम. थम्मन्ना के साथ उनके परिवार के सदस्य, कारोबारी साझेदार व सहयोगी शामिल थे। छापेमारी के दौरान मंजूनाथ, उनके चालक, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के परिसरों से 5.5 करोड़ रुपये नकद, 3.3 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा 7.8 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए गए। मंजूनाथ, बेल्लारी से पूर्व सांसद वाई. देवेंद्रप्पा के पुत्र हैं।

डीआईजी एमएन अनुचेत ने सूचना विभाग के कमिश्नर का पद संभाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। आईपीएस अधिकारी डीआईजी एमएन अनुचेत ने गुरुवार को सूचना और जनसंपर्क विभाग के नए कमिश्नर के तौर पर पदभार संभाला। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और -एडीजीपी हेमंत एम. निंबालकर, जो अब तक इस विभाग के कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, ने उन्हें पद का कार्यभार सौंपा। इस मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने नए कमिश्नर को शुभकामनाएं दीं।

विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं में आत्म-बोध और राष्ट्रीय चेतना आवश्यक : राज्यपाल

बेंगलूरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वे बेंगलूरु स्थित एमईएस (एमईएस) स्वायत्त कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित 'विकसित भारत 2047: आत्म-साक्षात्कार से राष्ट्र निर्माण तक' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, विकसित भारत 2047 की परिकल्पना मात्र एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा और प्रतिबद्धता है। जैसे-जैसे देश अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, विकास को केवल आर्थिक तरक्की के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक नवाचार, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों का समावेश होना अनिवार्य है।

गहलोत ने विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी के संतुलित एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ये विषय अलग-अलग नहीं रह गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इसी बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है। प्राचीन भारतीय सूक्ति सा विद्या या विमुक्तये (शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समाज से गरीबी, असमानता और भेदभाव को समाप्त कर लोगों को सशक्त बनाना है।

राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को रेखांकित करते हुए कहा कि जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण के जरिए अपनी क्षमताओं और कर्तव्यों को समझ लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने लगता है। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने और आत्मविश्वास, अनुशासन, त्याग व सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

कावेरी नदी में डूबने से चार महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मांड्या। कर्नाटक के मांड्या जिले में बुधवार को कावेरी नदी के तट पर कथित तौर पर सेल्फी लेने के दौरान चार महिलाओं सहित पांच लोग तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए, जिससे डूबकर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान श्वेता (37), चैत्रा (19), प्रियंका (28), विजयम्मा (45) और उनकी कार के चालक महेश (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृत चारों महिलाएं एक ही परिवार की थीं। यह घटना जिले के मुत्तथी के पास हुई। पुलिस के अनुसार, इन लोगों ने बेंगलूरु से एक कार किराये पर ली थी और वे मुत्तथी अंजनेयस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करने आई थीं। मंदिर के दर्शन करने के बाद वे तस्वीरें खिंचवाने के लिए कावेरी नदी के किनारे चली गईं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नदी तट पर सेल्फी लेने के दौरान वे नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गईं और डूब गईं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाकर सभी शवों को नदी से बाहर निकाला। मामले की जांच की जा रही है।

कांग्रेस आलाकमान ने शिवकुमार को मंत्री पद के लिए 'लॉबिंग' पर ध्यान न देने का निर्देश दिया

बेंगलूरु। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को निर्देश दिया है कि वह राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद के इच्छुक नेताओं की ओर से की जा रही 'लॉबिंग' पर ध्यान न दें। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वह नेताओं की ओर से मंत्री पद के लिए समर्थकों के विरोध-प्रदर्शन या अन्य तरीकों से दबाव बनाने की कोशिशों पर रोक लगाएं। सूत्रों के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद पाने की चाहत रखने वाले नेताओं के बढ़ते दबाव के बीच बुधवार को पार्टी आलाकमान के एक प्रतिनिधि ने शिवकुमार से बात की।

तमिलनाडु ने बिजली क्षेत्र के लिए 49,000 करोड़ रुपए की रूपरेखा तैयार की

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के ऊर्जा संसाधन एवं विधि मंत्री आर. निर्मल कुमार ने बृहस्पतिवार को राज्य के बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर एक 'श्वेत पत्र' जारी किया, जिसमें अवसंरचना को स्थिर करने, वित्तीय घाटे को पाटने और 20,000 रोजगार सृजित करने के मकसद से 49,532 करोड़ रुपए की रूपरेखा बनाई गई है।

मंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक राज्य के बिजली क्षेत्र पर कुल बकाया कर्ज 2,47,130 करोड़ रुपए रहा। उपभोक्ताओं की संख्या 2001 में 143.51 लाख थी, जो 2026 में बढ़कर 351.73 लाख हो गई है।

इसके अनुरूप, अधिकतम बिजली मांग 2001 में 6,687 मेगावाट थी, जो 2026 में बढ़कर 21,307 मेगावाट के दैनिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

मंत्री ने रूपरेखा को लेकर कहा कि इसमें 469 नए उपकेंद्र स्थापित करना, पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और 20,449 से अधिक पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष भर्ती योजना लागू करना शामिल है।

तुंगभद्रा बांध के सभी 33 'स्पिलवे गेट' खोले गए, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने किया उद्घघाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोप्पल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को यहां तुंगभद्रा बांध पर नये 33 'स्पिलवे गेट' का उद्घाटन किया। कोप्पल जिले के मुनीराबाद तालुका स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में तीनों राज्यों के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। आयोजन जल संसाधन विभाग और तुंगभद्रा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

कार्यक्रम से पहले नेताओं ने बांध क्षेत्र का दौरा किया, वहां विशेष पूजा-अर्चना की और बांध के 17, 18, 19 तथा 20 नंबर के गेटों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने शिलापट्ट का अनावरण किया। कोप्पल जिले में स्थित बांध का एक 'क्रेस्ट गेट' (19वां गेट) अगस्त 2024 में चेन लिंक टूट जाने के कारण बह गया था। इसके बाद बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था। यह घटना मानसून के दौरान भारी जल प्रवाह के बीच हुई थी।

इसके बाद हाइड्रो-मैकेनिकल इंजीनियर एन. कन्हैया नायडू के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने बह चुके 19वें गेट की जगह अस्थायी 'स्टॉप-लॉग' गेट को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। यह कार्य लगभग एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया गया था। इसके बाद विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर सभी 33 गेटों को बदल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। जल संसाधन मंत्री रामालिंग रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि अत्याधुनिक नए 'क्रेस्ट गेट' को लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और लगभग 51 करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए ये नए गेट अगले 55 से 60 वर्षों तक उपयोग में रहेंगे।

गंगा- कावेरी नदियों को जोड़ दिया जाए तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा : चंद्रबाबू नायडू

होसपेट (कर्नाटक)/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक में कहा कि अगर गंगा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा।तुंगभद्रा परियोजना के तहत 33 नए 'क्रेस्ट गेट' का उदघाटन करने के बाद यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के जरिए ''उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ा गया''।नायडू ने कहा,''अगर देश में गंगा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा।'' उन्होंने कहा कि गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की जरूरतें पूरी होंगी।

कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने नदी जल विवादों का हल तलाशने का संकल्प लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोप्पल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बृहस्पतिवार को नदी जल बंटवारे के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का संकल्प लिया। उन्होंने साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की भागीदारी से जल संकट का स्थायी समाधान खोजने का निर्णय लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के ए. रेवंत रेड्डी के बीच सहमति बनी। तीनों मुख्यमंत्री, यहां तुंगभद्रा बांध के नये 33 'स्पिलवे गेट' के उद्घाटन के दौरान पाटिल से मिले थे। पाटिल ने उद्घाटन के बाद यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक समय था जब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जल बंटवारे के मुद्दों को लेकर लगातार विवाद में रहते थे। बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी और कोई भी एक साझा मंच पर साथ नहीं आ रहा था। लेकिन आज का दिन अच्छा है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर मौजूद हैं। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि वे आपस में विवाद नहीं करेंगे।

पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताई है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा और जो व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं, उनके तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो तथा सभी को उनके हिस्से का उचित पानी मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़कों के माध्यम से देश को जोड़ रहे हैं और इसी तरह जल परियोजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ना चाहते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज तीनों नेताओं ने इस दिशा में मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पाटिल ने गाद जमने की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ऐसी रिपोर्ट हैं, जिनमें जिक्र है कि देश के 6,500 बांधों में से लगभग 15 प्रतिशत भंडारण क्षमता गाद जमा होने के कारण कम हो गई है। उन्होंने कहा कि तुंगभद्रा बांध ने भी इसी कारण अपनी क्षमता का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खो दिया है। पाटिल ने कहा, हमारे मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना तैयार की है। हमने तीनों मुख्यमंत्रियों को बताया है कि हम गाद निकालने की योजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। राज्य इस कार्य को पूरा करेंगे, जबकि हम उन्हें तकनीकी सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे। इसके परिणामस्वरूप तुंगभद्रा बांध की जल भंडारण क्षमता में 25-30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। पाटिल ने तीनों मुख्यमंत्रियों के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, जिस तरह उन्होंने बिना किसी आपत्ति के और वित्तीय सहयोग के साथ बांध के 33 गेट बदलने में सहयोग किया, मुझे विश्वास है कि उनके सामूहिक प्रयासों से गाद निकालने की परियोजना भी जल्द पूरी हो जाएगी।

शिवकुमार ने कहा कि तीनों राज्यों ने मिलकर तुंगभद्रा नदी बेसिन के किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक सहमति वाला निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, हमने कृषक परिवारों की सुरक्षा और संरक्षण के तरीकों पर चर्चा की। इसमें किसान नेताओं द्वारा इस बांध में पानी बचाने को लेकर की गई अपील भी शामिल थी। नवली जलाशय और गाद निकालने के मुद्दे सहित सभी विकल्पों पर चर्चा करने के बाद हम सभी एक सहमति वाले निर्णय पर पहुंचे हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमने करीब एक घंटे तक जो चर्चा की, वह देश की सिंचाई व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के इतिहास में दर्ज होगी। उन्होंने कहा, हमारा पानी, हमारा अधिकार की भावना के तहत हमने तीनों राज्यों के किसानों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने नदियों को आपस में जोड़ने की वकालत करते हुए कहा कि गंगा से लेकर कावेरी तक की नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एक बार ऐसा हो गया तो कोई भी भारत की प्रगति को रोक नहीं पाएगा। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा जरूर होगा।

इस बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री से तुंगभद्रा नदी के अंतरराज्यीय जल बंटवारे के मुद्दे का जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के गडवाल, आलमपुर व पालमुरु क्षेत्रों में किसान राजोलीबंडा डायवर्जन योजना (आरडीएस) के तहत आवंटित 17.9 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) पानी में से केवल पांच-छह टीएमसी फीट पानी का ही उपयोग कर पा रहे हैं।

रेड्डी ने कहा कि विभिन्न कारणों से आवंटित 10 टीएमसी फीट अतिरिक्त पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने पहले ही तुंगभद्रा नदी में गाद जमा होने और पानी के आवंटन से जुड़े मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के संज्ञान में लाया है। रेड्डी ने कहा, बैठक में हमने जल संकट का स्थायी समाधान खोजने का निर्णय लिया।

इसरो isro
भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो)
द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी)
निर्माण एवं अनुरक्षण समूह
80 फीट रोड, एचएएल II चरण, बेंगलूरु-560008 फोन: 080-25037203/080-2503214

दिनांक: 25.06.2026

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए नग दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं	कार्य का नाम व निविदा विवरण	निविदा का अनुमानित मूल्य	अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी)	कार्य समापन अवधि
1	आईटीपीएँफ़ सुविधा, एलपीएससी, तुमकूरु के लिए युपीएस सिस्टम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य - इनपुट और आउटपुट केबल सिस्टम उपलब्ध कराना NIT No. LPSC(B)/CMD/02/2046/ E/MI/009/2026-27 Date : 25.06.2026	रु. 19.87 लाख	रु. 39,740/-	20 दिन
	निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि	25.06.2026 को 18.30 बजे से 03.07.2026 को 23.59 बजे तक		
	बोली स्पष्टीकरण	25.06.2026 को 20.00 बजे से 06.07.2026 को 10.00 बजे तक		
	बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख	06.07.2026 को 17.00 बजे तक		
	निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	07.07.2026 को 11.00 बजे तक		
	निविदा खोलने की नियत तारीख और समय	07.07.2026 को 11.30 बजे से		

पात्रता मानदंड और अन्य ब्यौरे के लिए इच्छुक निविदाकार विस्तृत सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी) देखे जिसे वेबसाइट www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली प्रपत्र औप अन्य ब्यौरे वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। www.isro.gov.in, www.lpsc.gov.in

ह/- प्रमुख सीएमडी, एलपीएससी(बी)

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने किया पीटीईटी प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य के 944 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विवि द्वारा आयोजित पीटीईटी परीक्षा 2026 का परीक्षा परिणाम गुरुवार को जयपुर में उपमुख्यमंत्री एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद ने घोषित किया । इस अवसर पर मुख्य समन्यवक एवं कुलगुरु प्रोफेसर बी.एल. वर्मा भी उपस्थित रहे। विक्रम राठौड़ ने बताया कि 600 में से 509 अंक प्राप्त कर भरतपुर के कार्तिक कुमार गर्ग और चुरू के जयप्रकाश बिस्सू संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय स्थान पर उदयपुर के मनोज नागदा रहे, जिन्हें 600 में से 508 अंक मिले और तृतीय स्थान पर नागौर के युवराज रहे जिन्हें 600 में से 507 अंक मिले। परिणाम घोषित करने के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने टॉपर विद्यार्थियों से मोबाइल पर वार्ता की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उपमुख्यमंत्री ने वीएमओयू को गुड गवर्नेंस के लिए भी बधाई प्रदान की। कार्यक्रम में पीटीईटी समन्वयक प्रो. क्षमता चौधरी, डॉ. संदीप हुडा, डॉ. अकबर अली, विवि के अन्य कार्मिक व मीडियाकर्मी मौजूद रहे।

इस अवसर पर डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा प्रदेश की प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पीटीईटी-2026 में सफल सभी अभ्यर्थी भविष्य में आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी भावी शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर संस्कारवान बनाएंगे।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कुलगुरु प्रोफेसर वर्मा के निर्देशन में पीटीईटी परीक्षा के सफल आयोजन और कुशल प्रबंधन के साथ महज 10 दिनों में समयबद्ध परीक्षा परिणाम जारी करने की उपलब्धि के लिए सम्पूर्ण टीम को शुभकामनाएं प्रदान की।

कुलगुरु प्रो. बी.एल. वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमारा उद्देश्य प्रदेश में ऐसी आदर्श शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों से समृद्ध करे। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बीएड संस्थानों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वे स्वयं को एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित करें।

पीएम-जनमन योजना के कार्यों में लाएं गति, गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण हो कार्य : वी. श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम-जनमन के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विशेष रूप से जनजातीय समूह परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाले सभी कार्यों को उन्होंने कहा कि शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क एवं सामुदायिक अधोसंरचना से जुड़े कार्य जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारशिला हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करते हुए मार्च 2027 तक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा लाभार्थियों को समय पर सभी किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क संपर्क जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए । उन्होंने संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें।

बैठक में बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्वीकृत सभी केन्द्रों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र जनजातीय क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी के एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जहां मां-बाड़ी केन्द्र, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, वन धन केन्द्र, पंचायत संबंधी सेवाएं तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियां एक ही परिसर में संचालित की जा रही है। मुख्य सचिव ने छात्रावास निर्माण एवं संचालन की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत सभी हॉस्टलों का निर्माण पीएम-जनमन के निर्धारित डिज़ाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संचालित छात्रावासों में पात्र बच्चों का अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा उनके संचालन की नियमित समीक्षा की जाए।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा तथा शैक्षणिक वातावरण की भी सतत मॉनिटरिंग करे । बैठक में पाइप्ड वाटर एवं कम्युनिटी वाटर सप्लाई परियोजनाओं तथा पीवीटीजी परिवारों को दिए जा रहे पेयजल कनेक्शनों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र परिवारों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत संचालित सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग मिशन मोड में कार्य करते हुए लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की प्रगति का प्रत्यक्ष लाभ जनजातीय परिवारों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। इस अवसर पर वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, टीएडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव , जल जीवन मिशन निदेशक राजन विशाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल बागड़े ने विश्व धरोहर कुम्भलगढ़ दुर्ग का किया अवलोकन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध कुम्भलगढ़ दुर्ग स्थित महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग के विभिन्न भागों का पैदल ही अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता एवं स्थापत्य कला की सराहना की। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने दुर्ग की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाएं। राजस्थान की दुर्ग संस्कृति से जुड़ी महान विरासत से नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। उन्होंने दुर्ग की विशाल प्राचीर तथा वहां के भव्य महलों, कुंभा के उपासना स्थल शिव मंदिर आदि को विश्व धरोहर के रूप में प्रचारित प्रसारित किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल बागड़े ने कुम्भलगढ़ दुर्ग को अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण एवं संवर्धन को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है तथा भावी पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दुर्ग पर आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री खुद करें रिफाइनरी की मॉनिटरिंग : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखे प्रहार किए हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित राजस्थान दौरे से पहले गहलोत ने रिफाइनरी परियोजना की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को सचेत किया है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में आईओ (जांच अधिकारी) के मना करने के बावजूद ऊपर से दबाव डालकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। झच के दौरे से पहले उच और मुख्य सचिव खुद करें रिफाइनरी की मॉनिटरिंग, दोबारा न हो बदनामी अशोक गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना को लेकर राज्य सरकार को पूरी तैयारी रखने की सलाह दी है।

लगातार ट्रायल की मांग: गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री को तीन-चार दिन पहले और मुख्य सचिव को कम से कम दो दिन पहले मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए। दो-तीन दिन लगातार ट्रायल करवाकर सभी तकनीकी खामियां दूर की जानी चाहिए। पिछली घटना से लें सबक: पूर्व मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि पिछली बार प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रिफाइनरी परिसर में आग लगने की घटना हुई थी, जिससे पूरे राजस्थान की बदनामी हुई थी। इस बार ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए और सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

रिफाइनरी के इतिहास को रेखांकित करते हुए गहलोत ने भाजपा पर परियोजना को जानबूझकर अटकाने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के विशेष सहयोग से इस रिफाइनरी को मंजूरी मिली थी।

गहलोत ने आरोप लगाया कि बाद में आई भाजपा सरकार ने इस परियोजना को 5 साल तक रोके रखा। इसके कारण जो रिफाइनरी लगभग 37 हजार करोड़ रुपये में बननी थी, उसकी लागत अब बढ़कर करीब 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने मांग की कि जब प्रधानमंत्री मंच पर आएं, तो जनता को बताएं कि इस देरी और बढ़ी हुई लागत की जिम्मेदारी किसकी है?

सनातन संस्कृति सर्व कल्याण की सोच से जुड़ी है : राज्यपाल

पाली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सनातन संस्कृति अपने लिए नहीं लोक कल्याण की सोच से जुड़ी है। उन्होंने शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिव का अर्थ है, सर्व कल्याण। इसलिए इस अवसर पर हम समग्र कल्याण की सोच रखते हुए कार्य करने का संकल्प लें। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम संस्कृति बताते हुए कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरा है। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को पाली जिले के सादड़ी में अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ एवं स्वामी करपात्री फाउण्डेशन के तत्वावधान में आयोजित नागेश्वर महादेव, शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, 12 ज्योतिर्लिंग महिमा एवं 21 कुण्डीय विलक्षण महारुद्र महायज्ञ कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शक्ति के साथ भक्ति भाव भी देखने को मिलता है । उन्होंने इस अवसर पर भगवान शिव आदि योगी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एवं सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिले चिन्ह तथा वर्तमान भारतीय सनातन संस्कृति पर विस्तार से प्रकाश डाला। राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं एवं धार्मिक मूल्यों के संरक्षण के महत्व पर बल दिया। राज्यपाल मंदिर परिसर गए जहाँ उन्होंने नागेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु ,संतो व यज्ञशाला,रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन भी किये।

भजनलाल शर्मा ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान, पेंशन बढ़ाकर 25 हजार करने की घोषणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों के योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय था, जब संविधान की मूल भावना, नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर गंभीर प्रहार किए गए। असहमति की आवाजों को दबाया गया और हजारों लोकतंत्र सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। इसके बावजूद लोकतंत्र सेनानियों ने अपने साहस, त्याग और अटूट संकल्प से लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का प्रतीक है तथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र के इन प्रहरियों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा सहायता राशि को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी और लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे।

मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक अवार्ड दिया

जयपुर। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के दिशा निर्देशन में प्रदेश में ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन की राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने पर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया) द्वारा रिकॉर्ड श्रेणी में दर्ज कर गुरूवार को विद्युत भवन में वैश्विक सम्मान पत्र प्रदान किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युतगृहों की कोयला आधारित कुल क्षमता 7580 मेगावाट क्षमता की 23 इकाईयों से 2 जून, 2026 को उत्पादन निगम के गठन से लेकर अब तक का राज्य स्तर पर उच्चतम 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की थी। प्रदेश में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा कार्य संभालते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ऊर्जा पर फोकस करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए गए थे।यह वैश्विक अवार्ड हीरालाल नागर के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी मार्गदर्शन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभूतपूर्व प्रयासों को समर्पित करते हुए संयुक्त रूप से दिया गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी को भी निगम की इस ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन हासिल करने की उपलब्धि पर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स संस्था के मैनेजर अरिहंत उपाध्याय एवं कोऑर्डिनेटर गरिमा जैन द्वारा रिकॉर्ड श्रेणी में दर्ज कर आज विद्युत भवन में वैश्विक सम्मान पत्र सौंपा गया। हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऊर्जा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युतगृहों ने 7580 मेगावाट क्षमता की सभी 23 थर्मल इकाइयों से 7171 मेगावाट का उच्चतम विद्युत उत्पादन दर्ज किया था।

रणथम्भौर की दीर्घायु बाघिन टी-39: साहस और जीवटता की जीवित मिसाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन मछली के बाद अब बाघिन टी-39 ने अपने असाधारण जीवट से नई मिसाल कायम की है। लगभग 18 वर्ष की आयु में टी-39 रणथम्भौर की सबसे दीर्घायु बाघिनों में शामिल हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आमतौर पर जंगल में बाघ 10 से 15 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, लेकिन टी-39 ने बिना किसी बाहरी सहायता या मानवीय हस्तक्षेप के इतना लंबा जीवन जीकर अद्भुत जीवटता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रमाण दिया है। मछली बीस साल की उम्र तक जीवित रही थी। वन विभाग के अनुसार हाल के समय में टी-39 के व्यवहार में बदलाव देखा गया है। वह अब जंगल के बाहरी क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रही है। यह बढ़ती उम्र का संकेत हैं, जब बाघिनें शांत स्थानों की तलाश करती हैं और अपने क्षेत्र से धीरेधीरे दूरी बना लेती हैं।

बाघिन टी39 अब गाढ़ा डूब, पटवा बावड़ी और कुंडी क्षेत्र में देखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग की टीमें उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि उसकी और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के उप वन संरक्षक मानस सिंह ने कहा, टी-39 ने अपने जीवनकाल में तीन बार शावकों को जन्म दिया जो उद्यान के बाघों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है।

उन्होंने बताया कि टी39 की तुलना प्रसिद्ध बाघिन 'मछली' से की जाती है, जिसने संरक्षण की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन टी-39 का जीवन और भी उल्लेखनीय है क्योंकि उसने

पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थितियों में इतना लंबा जीवन जिया है। मानस ने बताया कि टी39 को कोई सहायता नहीं दी गयी और ना ही खाने की व्यवस्था की गयी। इसके अलावा वह ना ही कभी बीमारी हुई और उसे कोई चिकित्सा उपलब्ध भी नहीं कराई गई। मानस ने कहा, टी-39 का जीवन साहस, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। उसने यह साबित किया है कि वन्यजीव अपने प्राकृतिक वातावरण में भी लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि रणथम्भौर के लिए टी-39 सिर्फ एक बाघिन ही नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत है। उपवन संरक्षक ने बताया कि टी-39 की तुलना अक्सर प्रसिद्ध बाघिन मछली (टी-16) से की जाती है, जिसने करीब 20 वर्षों तक जीवित रहकर दुनिया के सबसे वृद्ध बाघों में जगह बनाई थी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वन विभाग के अनुसार, बाघिन मछली का सबसे चर्चित कारनामा 2003 में सामने आया था जब उसने रणथम्भौर की एक झील में 14 फुट लंबे मगरमच्छ से मुकाबला कर उसे मार डाला था। इस घटना ने उसे क्रोकोडाइल किलर और लेडी ऑफ द लेक की उपाधि दिलाई। मछली ने 11 शावकों को जन्म दिया और उनकी परवरिश कर रणथम्भौर की बाघ आबादी को स्थिर और मजबूत बनाए रखा। वर्ष 2016 में उसकी मौत हो गयी।

मानसून से पहले अलर्ट पर एसडीआरएफ

राजस्थान के 35 जिलों में रवाना की गईं 70 रेस्क्यू टीमें

जयपुर। आगामी मानसून सत्र के दौरान राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न होने वाली किसी भी सम्भावित आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल(एसडीआरएफ) ने कमर कस ली है। प्रदेशवासियों की सुरक्षा और आपदा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए आज 25 जून को एसडीआरएफ की सभी कंपनियों से गठित कुल 70 रेस्क्यू टीमों को आपदा राहत उपकरणों के साथ संभावित बाढ़ प्रभावित 35 जिलों के लिए रवाना किया गया है।

जयपुर स्थित एसडीआरएफ कंट्रोल रूम से राज्य आपदा प्रतिसाद बल के कमान्डेंट राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने इन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के अलावा अन्य जिलों में तैनात होने वाली रेस्क्यू टीमों को संबंधित कंपनी मुख्यालयों से कंपनी प्रभारियों द्वारा रवाना किया गया है। कमान्डेंट सिसोदिया ने बताया कि अत्यधिक वर्षा, जलभराव और नदियों/बांडों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति में नागरिकों का जीवन बचाना एसडीआरएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संविधान की रक्षा के बहाने 'लोकतंत्र-विरोधी गतिविधियां' करते हैं कांग्रेस नेता : नड्डा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा ने बृहस्पतिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का दावा करते हुए लोकतंत्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।

जे. पी. नड्डा ने यहां ज्ञान भवन में 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समय-समय पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। उन्होंने कहा, ''आज कांग्रेस हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान की प्रति लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले राहुल गांधी को अपनी दादी के उन कृत्यों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने संविधान को तार-तार कर दिया था।''

नड्डा ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया तथा अदालतों से सरकारी प्रतिबंधों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, ''कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन ने लोकतंत्र को अक्सर राजनीतिक सुविधा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। उनकी राजनीतिक

सोच हमेशा लोकतंत्र विरोधी रही है।''

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर संवैधानिक प्रावधानों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''जवाहरलाल नेहरू ने आठ बार राष्ट्रपति शासन लगाया। इंदिरा गांधी ने करीब 50 बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर और सीमित अवधि के लिए मणिपुर को छोड़कर राष्ट्रपति शासन का व्यापक इस्तेमाल नहीं हुआ।''

नड्डा ने आरोप लगाया कि 'इंडिया' गठबंधन की गतिविधियां ''राष्ट्र को मजबूत करने की सोच'' नहीं बल्कि ''सत्ता प्राप्ति'' की राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए ''अत्याचारों'' को याद रखना जरूरी है ताकि भारतीय लोकतंत्र, जिसने उसे कुचलने की कोशिश करने वालों को पराजित किया, भविष्य में भी मजबूत बना रहे और ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

नड्डा ने कहा, ''कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि यदि इंदिरा गांधी आज जीवित होतीं तो भाजपा पर प्रतिबंध लगा देतीं। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। यदि उनका बस चलता तो वे आरएसएस और अन्य राष्ट्रभक्त संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा देते।'' उन्होंने लोगों से कांग्रेस को हमेशा सत्ता से दूर रखने की अपील करते हुए कहा कि इससे आपातकाल जैसे ''काले दिन'' दोबारा नहीं लौटेंगे।

नड्डा ने दावा किया कि आपातकाल के दौरान 1.31 लाख से अधिक लोगों को बिना न्यायिक समीक्षा के जेल में बंद किया गया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन ने भी इस स्तर के अत्याचार नहीं किए थे। उन्होंने कहा, ''आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) का इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी उस पैमाने पर नहीं हुआ था, जिस पैमाने पर आपातकाल में किया गया।''

कांग्रेस ने आपातकाल के लिए अभी तक ''बिना शर्त माफी'' नहीं मांगी: नितिन नवीन

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था और विपक्षी पार्टी ने इसके लिए देश से अभी तक ''बिना शर्त माफी'' नहीं मांगी है। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू रहा था, जिससे कार्यपालिका को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गईं और राज्यों का अधिकार केंद्र के नियंत्रण में आ गया। नवीन ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था, जिस दौरान ''संविधान की आत्मा को कुचलने'' का प्रयास किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। इसके बाद राष्ट्रहित नहीं, बल्कि सत्ता हित को प्राथमिकता दी गई।'' उन्होंने कहा, ''एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास किया गया।''

पश्चिम बंगाल सरकार पूर्व की अनियमितताओं, कर्ज के बोझ पर श्वेत पत्र लाएगी : स्वप्न दासगुप्ता

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं, अधूरी परियोजनाओं और वित्तीय कुप्रबंधन पर विभागवार श्वेत पत्र जारी करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। विधानसभा में दासगुप्ता ने राज्य के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने उन हालात की जानकारी जनता के सामने रखने का फ़ैसला किया है जिनकी वजह से राज्य पर कर्ज़ का बोझ बढ़ा और कई परियोजनाओं में देरी हुई। उन्होंने कहा, ''हम हर विभाग के लिए अलग-अलग श्वेत पत्र लाने पर विचार कर रहे हैं। वित्त विभाग यह बताएगा कि किस तरह के कुप्रबंधन की वजह से इतना भारी कर्ज का बोझ बढ़ा। दूसरे विभाग यह बताएंगे कि परियोजनाएं क्यों अधूरी रह गईं और क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई।'' मंत्री ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएंगी, जिन पर उनके अनुसार पहले जनता का पर्याप्त ध्यान नहीं गया था।

अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए सिंधी समुदाय की ओर से दान की गई 200 किलोग्राम चांदी को लेकर उठे सवाल

लखनऊ/भाषा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दिये गये दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच सिंधी समुदाय के एक प्रतिनिधि ने जनवरी 2021 में मंदिर के लिए दान की गई लगभग 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों के इस्तेमाल के बारे में पारदर्शिता की मांग की है। सिंधी समाज के प्रतिनिधि और विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष डॉक्टर राजू वी. मनवानी ने बृहस्पतिवार को लेह में 'पीटीआई वीडियो' से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और विदेश में रहने वाले सिंधी समुदाय के लगभग 200 श्रद्धालुओं ने राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को चांदी की ये ईंट दान की थीं। मनवानी के मुताबिक श्रद्धालुओं ने अलग-अलग मात्रा में चांदी की ईंट दान की थीं। उन्होंने कहा कि किसी ने एक तो किसी ने 10 ईंट दी थी और ये ईंट मंदिर परियोजना में इस्तेमाल के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सौंपी गई थीं। मनवानी बताया कि दान लेते समय कोई रसीद जारी नहीं की गई थी।

'लोकतंत्र सेनानियों' को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा जल्द : आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार लोकतंत्र को बचाने वाले 'लोकतंत्र सेनानियों' के लिए जल्द ही प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने आपातकाल की 51वीं बरसी 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 'लोकतंत्र सेनानियों' के स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना की।

एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 'लोकतंत्र सेनानियों' का सम्मान करते हुए गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि

'लोकतंत्र सेनानियों' ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल की यातनाएं सहीं, इसलिए प्रदेश में जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित सरकार आई तो 'लोकतंत्र सेनानियों' के सम्मान के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।

प्रदेश में 3,780 'लोकतंत्र सेनानी' तथा 1,461 उनके आश्रित हैं। सरकार वर्ष 2018 से 'लोकतंत्र सेनानियों' व मरणोपरांत उनके आश्रितों को प्रत्येक माह 20 हजार रुपए की सम्मान राशि दे रही है। साथ ही 'लोकतंत्र सेनानी' या उनके उत्तराधिकारी (पति अथवा पत्नी) को एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। 'लोकतंत्र सेनानियों' को राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

योगी ने कहा कि अब सरकार लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी उलब्ध कराने जा रही है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानी के दिवंगत होने पर उनका अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश व लोकतंत्र के हित में काम करेगा, सरकारें उन्हें सम्मानित करेंगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 'लोकतंत्र सेनानियों' का सम्मान किया।

कोलकाता गोदाम हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 10 हुई, खोज के लिए सेना ले रही रडार की मदद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। कोलकाता के दक्षिणी हिस्से के तारातला इलाके में गोदाम ढहने की घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 10 हो गई। घटना के करीब 21 घंटे बाद भी बचाव दल, सेना की उन्नत ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) प्रणाली की सहायता से, मलबे में गहन तलाश अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बचाव अभियान से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सुबह मलबे से पांच और लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसके बाद मलबे से बाहर निकाले गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कृष्णा चौधरी (30), रोहित चौधरी (40), राहुल चौधरी (17), चंद्रमा चौधरी (60), पप्पू रजक (40), असगर हुसैन (55), साहिल सरदार (17) और घी कुमार (17) के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। यह गोदाम शहर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के स्वामित्व वाली पट्टे पर दी गई भूमि पर बनाया जा रहा था। घायलों का इलाज कर रहे एसएसकेएम अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह एक और व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सभी पीड़ितों का विवरण जुटाने और उनकी आधिकारिक पुष्टि करने के प्रयास जारी हैं। राहत और बचाव कार्य पूरी रात जारी रहा और इसकी निगरानी स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम, कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदा तथा कोलकाता नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडेय सहित राज्य सरकार और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने की।

मोदी सरकार में शिक्षा व्यवस्था से छात्रों का भरोसा टूटा: गोगोई

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा संबंधी कथित अनियमितताओं की बार-बार सामने आ रही घटनाओं को शिक्षा व्यवस्था की ''बड़ी संस्थागत विफलता'' करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे छात्रों का भरोसा टूट गया है।

छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गोगोई ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षाओं में व्यवधान की बार-बार होने वाली घटनाओं से छात्रों के बीच यह धारणा बन गई है कि यह समस्या कुछ व्यक्तियों की गलती नहीं, बल्कि ''व्यवस्थागत'' है। उन्होंने कहा, ''भारत के छात्रों का भरोसा टूट गया है। इतने टूटे हुए सपनों की जिम्मेदारी कौन लेगा?'' लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गोगोई ने कहा, ''यदि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके माता-पिता आर्थिक बोझ झेल रहे हैं तो किसी न किसी को इसकी जवाबदेही लेनी होगी।'' कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) द्वारा आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के 40 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 'छात्रों की गूंज' की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत छात्रों से संवाद स्थापित कर प्रश्नपत्र लीक, भर्ती में देरी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यापक मुद्दों पर उनकी राय और शिकायतें एकत्र की जाएंगी। एनएसयूआई नेताओं के अनुसार, अभियान की शुरुआत देशभर में 28 स्थानों पर एक साथ की गई है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में संपर्क कार्यक्रम, टाउन हॉल बैठकें, नुक्कड़ सभाएं, जनसंवाद और पर्चा वितरण अभियान चलाए जाएंगे।

आरजी कर हत्या-दुष्कर्म मामला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की प्रगति पर नाराजगी जताई

कोलकाता/भाषा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 में सरकारी आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की कथित साजिश की सीबीआई जांच की प्रगति पर बृहस्पतिवार को नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि पिछले जांच अधिकारी को हटाने के बाद सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी)से जांच कराने का आदेश दिया गया था ताकि मामले को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जा सके। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 मई को अदालत के निर्देश के अनुसार अबतक की गई जांच की वास्तुस्थिति रिपोर्ट पीठ के समक्ष पेश की।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने कहा, ''हमारे सामने पेश की गई रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं।''

भोजपुर मुठभेड़: न्यायिक आयोग गठित, दोषियों पर होगी कार्रवाई: सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर मुठभेड़ की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग का तत्काल गठन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पटना के ज्ञान भवन में 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना और संविधान के मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सहयोग शिविर का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में शिकायत का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 3.70 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3.20 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी आंदोलन के हर सेनानी और लोकतंत्र रक्षक को उचित सम्मान

दिया जाएगा तथा ऐसे पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो अब तक किसी कारणवश सम्मान और सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। केंद्र और बिहार की 'डबल इंजन' सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। दोनों नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा जेपी आंदोलन के सेनानियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन लगभग 50 वर्ष पहले देश ने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात भी देखा था। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था और इसी स्मृति को जीवित रखने के लिए देशभर में 'संविधान हत्या दिवस' मनाया जा रहा है।

चुनावों के बहिष्कार का सवाल नहीं, भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों एक ही टीम में: रमेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को किसी भी सूरत में चुनावों के बहिष्कार की संभावना को खारिज किया और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावी मैदान में केवल अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग से भी मुकाबला कर रही है।

रमेश ने 'पीटीआई वीडियो' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में क्रिकेट की उपमा देते हुए कहा, हम दूसरी टीम (भाजपा) और अंपायर (निर्वाचन आयोग) दोनों के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि अंपायर तटस्थ नहीं है और विरोधी टीम का हिस्सा बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहना चाहिए। यह

पूछे जाने पर कि 2029 का चुनावी परिदृश्य विपक्ष के लिए कैसा दिखता है और वह आयोग की तटस्थता को लेकर जिन सवालों को उठा रहा है, उनसे विपक्ष कैसे निपटेगा, तो रमेश ने कहा, '' क्रिकेट मैच में दो टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। यहां हम दूसरी टीम और अंपायर, दोनों के खिलाफ खेल रहे हैं। अंपायर विपक्षी टीम का हिस्सा है। आप क्या कर सकते हैं? मुख्य अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर, दोनों विपक्षी टीम का हिस्सा हैं।'' उन्होंने कहा, ''हां, यह कठिन स्थिति है। हमें चुनाव लड़ना है। चुनावों का बहिष्कार हमारे एजेंडे में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनावों का बहिष्कार करेगा। हमें चुनाव लड़ना होगा। हमें सरकार को बेनकाब करना जारी रखना होगा... अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा। कभी-कभी अदालतें मदद करती हैं, कभी-कभी वे मदद करने के लिए पर्याप्त साहस नहीं दिखातीं।'' रमेश ने कहा, ''यह लंबा संघर्ष होने वाला है... सफलता का कोई तात्कालिक मंत्र नहीं है। हमें लड़ते रहना होगा। हमें ये मुद्दे उठाते रहना होगा और मैं अब लोगों को सवाल उठाते हुए देख रहा हूं।'' उन्होंने कहा कि 12 साल पहले किसी न किसी कारण मोदी सरकार को समर्थन देने वाले तबके भी अब उस पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ''वर्तमान शासन के खिलाफ हास्य, व्यंग्य और चुटकुले बनाए जा रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोग अब डरे हुए नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि पहले भय और डराने-धमकाने का माहौल था, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं और अर्थव्यवस्था की समस्याएं सामने आ रही हैं।''

रेल मंत्रालय ने भाला और अन्य भारी खेल उपकरण रेल में ले जाने की स्वीकृति दी

नई दिल्ली/भाषा। खिलाड़ियों को अब रेल में भाला और भारी खेल के सामान ले जाने की इजाजत होगी, भले ही ये उपकरण तय आकार से बड़े हों। हालांकि पोल वॉल्ट के पोल को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में जारी एक सर्कुलर में रेल मंत्रालय ने रेल में गैर मानक आकार वाले बड़े और नाजुक खेल के सामान को ले जाने के लिए नियम बनाए हैं। यह छूट उन खबरों के बाद दी गई है जिनमें बताया गया था कि खिलाड़ियों को रेल से यात्रा करते समय गैर मानक आकार के सामान को ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्कुलर में कहा गया है कि भाले और खेल के अन्य बड़े सामान को निर्धारित माल ढुलाई शुल्क का भुगतान करने पर रेल में उपलब्ध सामान रखने की जगह में प्राथमिकता के आधार पर ले जाया जा सकता है। मंत्रालय ने साफ किया है कि सामान के लिए अधिकतम वजन की सीमा तय करने वाले मौजूदा व्यावसायिक सर्कुलर खेल के सामान पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते पार्सल निरीक्षण यह सत्यापित कर ले कि ले जाया जाने वाला सामान असल में खेल का सामान ही है। सर्कुलर में कहा कि पोल वॉल्ट के पोल को किसी भी कोच में ले जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

पेपर प्लेट फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर प्रकरण: यातना से एक श्रमिक की मौत, शव बैग में भरकर फेंकने का आरोप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुजफ्फरनगर (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक पेपर प्लेट निर्माण इकाई से 12 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जांचकर्ताओं ने पाया कि कैद किए गए श्रमिकों में से एक की कथित तौर पर यातना के कारण मौत हो गई और उसके शव को बाद में एक बैग में भरकर फेंक दिया गया था । पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह तथ्य उस मामले की जांच के दौरान सामने आया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित एक पेपर प्लेट फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद उजागर हुआ था।

एसएसपी के मुताबिक, मृत श्रमिक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अर्जुन की कथित तौर पर नवंबर 2025 में फैक्ट्री परिसर में यातना दिए जाने के बाद मौत हो गई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मौत के बाद उसके शव को

एक बैग में पैक कर फेंक दिया गया था। कुमार ने बताया कि इस खुलासे के बाद फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान और सुपरवाइजर शिवा त्यागी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि शिवा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी और फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान अब भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है। मामले की गहन जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया गया है। एसएसपी ने कहा कि टीम पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। इस बीच, फैक्ट्री से मुक्त कराए गए सभी 12 मजदूरों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है और उनका उपचार जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं के तहत मुक्त कराए गए श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। प्रशासन उनके बैंक खाते खुलवाने तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के प्रयास भी कर रहा है।

सुविचार

चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

आपातकाल को याद रखना क्यों जरूरी?

भारत में 25 जून, 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को हमेशा याद रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य कहा कि आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। उस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सख्त पाबंदियां थोपी गई थीं। कई राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर उन पर घोर अत्याचार किए गए थे। युवाओं को मालूम होना चाहिए कि जिस आज़ादी की खुली हवाओं में वे सांस ले रहे हैं, वह मुफ्त में नहीं मिली है। उसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, त्याग और बलिदान है। युवाओं को आपातकाल के बारे में इसलिए भी मालूम होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति खुद को सर्वशक्तिमान न समझने लगे। लोकतंत्र के सामने कई खतरे होते हैं। चाहे वे दिखाई न दें, लेकिन उनके अस्तित्व को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। उनमें से एक खतरा है- तानाशाही। जब शीर्ष पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और सत्ता के अहंकार में डूब जाता है तो उसके चापलूस सलाहकार ऐसी राय दे देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। हालांकि जनता जुल्म सहकर देर-सबेर ऐसे तानाशाहों का नशा उतार ही देती है। आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोंटने की कोशिशें खूब हुई थीं। आज कई लोग इंटरनेट के जरिए प्रसारित सच्ची-झूठी सामग्री को ही मीडिया समझकर अनर्गल टीका-टिप्पणी कर देते हैं। उन्हें आपातकाल में कलम के सिपाहियों के संघर्ष के बारे में जानना चाहिए। उस दौरान पत्रकारों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। सत्ता से टकराने वाले, कठोर सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर दबाव डालने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई हथकंडे अपनाए थे। कई बार ऐसी नौबत आती कि पत्रकार दिनभर भूखे-प्यासे रहकर लोगों से मिलते, उनकी तकलीफें जानते और रिपोर्ट तैयार करते। रात को जब रिपोर्ट पेज पर लगती तो एक सरकारी अधिकारी आकर उस पर कैंची चला देता था। अगले दिन वह हिस्सा पाठकों तक खाली पहुंचता था।

आपातकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक था- बड़े पैमाने पर चलाया गया नसबंदी अभियान। इसके तहत लाखों लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी। सरकारी कर्मचारियों पर नसबंदी के लक्ष्य पूरे करने का दबाव डाला गया था। लोगों को मजबूर किया जाता था कि अगर वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपनी नसबंदी करवाएं। ऐसे भी मामले आए, जब लोगों को यह कहकर सरकारी गाड़ियों में बैठाया गया कि 'आपको उपहार दिए जाएंगे।' बाद में उनकी नसबंदी कर दी गई। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया! आज जब केंद्र सरकार 'संविधान हत्या दिवस' मनाकर आपातकाल के क्रूरतापूर्ण अध्यायों को सामने ला रही है तो विपक्ष के राजनेताओं को दिक्कत हो रही है। उनके समर्थक अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिख रहे हैं कि 'वह दौर बीत गया ... अब उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है ... अगर बात करनी है तो रोजगार के बारे में करें।' सवाल है- उस दौर के बारे में बात क्यों न करें? कोई दौर बीत गया, इसका यह मतलब तो नहीं कि अब उसके बारे में सब चुप्पी साध लें? फिर तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश शासक दशकों पहले देश छोड़कर चले गए! रोजगार के बारे में बात जरूर होनी चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। इससे कौन इन्कार कर रहा है? हमें अपने अतीत से सबक लेना चाहिए। जो गलतियां पूर्व में हुईं, उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सदियों की गुलामी के बाद आजादी का सवेरा देखा था। हमारा कर्तव्य है कि इस आजादी को कायम रखें। इसकी हर तरह से रक्षा करें। किसी भी व्यक्ति, पार्टी, सरकार, संस्था और संगठन को यह मौका कभी न दें कि वह खुद को इस देश से बड़ा समझने का भ्रम पाल ले।

ट्वीटर टॉक

हर जगह अफ़रा-तफ़री मची हुई है। भाजपा शासित राज्यों में, जहाँ भी उनकी सरकारें हैं, वहाँ अफ़रा-तफ़री मची हुई है। इस तरह की लूट पहले कभी इस तरह सुनी, देखी या समझी नहीं गई। स्थिति बहुत गंभीर है। एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं।

-अशोक गहलोत

25 जून, 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है जब कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान की मूल भावना, नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश की। बोलने की आज़ादी पर पाबंदियां लगाई गई ।

-दिया कुमारी

जयपुर में 'संविधान हत्या दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इमरजेंसी के मुश्किल दौर में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष और बलिदान देश को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

-भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

शब्दों की शुचिता

भारतीयता के पोषक महामना पंडित मदनमोहन मालवीय, प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी विचारों और भावनाओं को देखना पसन्द करते थे। एक बार भ्रमण के दौरान मालवीय जी बंबई में रामेश्वरदास बिरला के आवास पर ठहरे हुए थे। उनके बंबई आगमन की सूचना पाकर पंडित रमापति मिश्र उनसे मिलने के लिए वहां चले आये। बातचीत के दौरान 'क्रोध' पर चर्चा चल निकली। मिश्रजी ने कहा, मालवीय जी मैं तो क्रोध से बचा हुआ हूं, आप बेशक मुझे सौ गालियां देकर देख लीजिये, मुझे फिर भी तनिक क्रोध नहीं आएगा।' महामना मुस्करा कर बोले, पंडितजी, क्षमा करें। यह मुझ से संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि आपकी सहनशीलता की परीक्षा तो एक सौ गालियां देने के पश्चात होगी, पर मेरा मुंह तो एक ही गाली देने पर मैला हो जाएगा।

सामयिक

ड्रग्स के दलदल में धंसती युवा पीढ़ी

योगेश कुमार गोयल
मोबाइल : 9416740584

अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस हमें यही संदेश देता है कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सतत सामाजिक आंदोलन है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी युवा शक्ति को नशे के अंधकार से मुक्त करना होगा।

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के सपनों, ऊर्जा और सृजनशीलता पर निर्भर करता है लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आने लगे तो यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लेती है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के सामने यही चुनौती खड़ी है। युवाओं की प्रतिभा, उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता और उनके भविष्य पर नशे का ऐसा ग्रहण लग रहा है, जो न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहा है। इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी मानवता को चेताने का अवसर है कि यदि नशे के बढ़ते दुष्चक्र को समय रहते नहीं रोका गया तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे।

भारत में नशे की समस्या अब महानगरों तक सीमित नहीं रही। यह गांवों, कस्बों, छोटे शहरों और यहां तक कि स्कूलों तथा कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। कभी माना जाता था कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल संपन्न वर्ग या शहरी संस्कृति की समस्या है लेकिन आज वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और इंजेक्शन के माध्यम से लिए जाने वाले नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति बताती है कि नशे का नेटवर्क अब समाज की हर परत तक पहुंच चुका है। आज का युवा अनेक प्रकार के दबावों से घिरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक तनाव, मानसिक अवसाद, अकेलापन और त्वरित सफलता की चाह उसे भीतर से कमजोर बना रही है। ऐसे में नशे के सौदागर युवाओं की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई बार मित्रों का दबाव, आधुनिक दिखने की चाह, रोमांच की तलाश या क्षणिक सुख का आकर्षण युवाओं को नशे की ओर धकेल देता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है लेकिन धीरे-धीरे यही जिज्ञासा लत और फिर विनाश का कारण बन जाती है।

इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने जहां ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, वहीं नशे के कारोबार को भी नए साधन उपलब्ध कराए हैं। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब नशे का सौदा किसी सुनसान गली तक सीमित नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे की पहुंच चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। आज देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं।

यह विडंबना ही है कि जिन परिसरों में देश के भविष्य का निर्माण होना चाहिए, वहां कुछ युवा अपने भविष्य को स्वयं नष्ट करने की राह पर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता और स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। कई युवाओं को यह भ्रम होता है कि नशा उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, रचनात्मक और आधुनिक बनाता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरणशक्ति प्रभावित होती है, एकाग्रता घटती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जो युवा अपने जीवन में बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है, वही नशे की गिरफ्त में आकर अपनी प्रतिभा और संभावनाओं को स्वयं नष्ट कर देता है। यही कारण है कि नशे को केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि मानव संसाधन के विनाश की समस्या माना जाता है।

नशीले पदार्थों का सबसे घातक प्रभाव यह है कि वे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से गुलाम बना देते हैं। एक बार लत लग जाने पर व्यक्ति उसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक मात्रा में नशा लेने लगता है। परिणामस्वरूप उसका शरीर कमजोर होने लगता है, भूख कम हो जाती है, वजन घटता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, नींद प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई मामलों में व्यक्ति आत्मघाती प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वालों के सामने खतरा और भी गंभीर होता है। एक ही सुई के बार-बार उपयोग से एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है।

नशे का अवैध व्यापार दुनिया के सबसे लाभकारी अपराधों में शामिल है। अरबों-खरबों रुपये का यह कारोबार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, आतंकवाद, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे नशीले पदार्थों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाली तस्करी की खेपें भारत के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ड्रग्स का यह अवैध कारोबार अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार माध्यम, फर्जी पहचान और डिजिटल भुगतान प्रणालियां तस्करों को नई ताकत प्रदान कर रही हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक पुलिसिंग से इस समस्या पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए तकनीकी, सामाजिक और कानूनी स्तर पर व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

भारत में हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए कड़े कानून मौजूद हैं लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती अभी भी बनी हुई है। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस, प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों को अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। शिक्षण संस्थानों को नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने होंगे। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दरअसल नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता, शिक्षा और सकारात्मक वातावरण है। यदि युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार, खेल, कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे नशे जैसे विनाशकारी रास्तों से दूर रह सकते हैं। हमें युवाओं को केवल नशे के दुष्परिणाम बताने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें जीवन का सकारात्मक उद्देश्य भी देना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस हमें यही संदेश देता है कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सतत सामाजिक आंदोलन है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी युवा शक्ति को नशे के अंधकार से मुक्त करना होगा। देश की युवा सोच पर लगा यह ग्रहण तभी हटेगा, जब सरकार, समाज, परिवार और स्वयं युवा मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के हाथों में नशे की पुड़िया नहीं, ज्ञान की पुस्तक हो; उनकी आंखों में नशे का धुंधलापन नहीं, सपनों की चमक हो; और उनकी सोच पर नशे का ग्रहण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का उज्ज्वल प्रकाश हो। यही नशा-मुक्त भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव भी।

नजरिया

टूटते रिश्ते, बुझती संवेदनाएँ और बढ़ते अपराध

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'

पति-पत्नी के संबंधों में बढ़ती कटुता भी चिंताजनक है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। लेकिन आज कई बार इसे केवल व्यक्तिगत सुविधा और अपेक्षाओं के दायरे में सीमित कर दिया जाता है। जब अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं, तब संबंधों में दरार आने लगती है। ऐसे समय में संवाद, परामर्श और धैर्य की आवश्यकता होती है।

हाल ही में पुणे के युवा उद्यमी केतन अग्रवाल की हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मात्र पच्चीस वर्ष की उम्र में जीवन के सुनहरे सपने संजोए एक युवक की हत्या उस समय हुई, जब वह अपने विवाह की तैयारियों में व्यस्त था। परिवार में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदारों के आने-जाने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अचानक आई इस दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। इससे पहले मेरठ, इंदौर और देश के कई अन्य शहरों में भी ऐसे मामले सामने आए, जहाँ प्रेम संबंधों, वैवाहिक विवादों या व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हत्या जैसी जघन्य घटनाएँ हुईं। इन घटनाओं ने समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों की वह पवित्रता कहाँ खो गई, जिसके सहारे परिवार और समाज की पूरी संरचना खड़ी होती है? क्या हम ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ असहमति का समाधान संवाद नहीं बल्कि हिंसा बनती जा रही है? रिश्ते मानव जीवन की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक रिश्तों के सहारे ही जीवन का सफर तय करता है। माता-पिता का स्नेह, भाई-बहनों का अपनापन, मित्रों का साथ और पति-पत्नी का विश्वास जीवन को अर्थ प्रदान करता है। लेकिन आज का समाज तेजी से बदल रहा है। आधुनिकता, तकनीक और भौतिक सुख-सुविधाओं ने जीवन को आसान तो बनाया है, परंतु भावनात्मक स्तर पर मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक अकेला और असुरक्षित होता जा रहा है। रिश्तों में धैर्य, त्याग और समझदारी की जगह जल्दबाजी, स्वार्थ और अहंकार ने लेना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि छोटी-छोटी बातें बड़े विवादों का रूप धारण कर लेती हैं।

केतन अग्रवाल की हत्या जैसी घटनाएँ केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हैं, बल्कि वे समाज की उस मानसिकता को उजागर करती हैं, जिसमें लोग समस्याओं का समाधान वैधानिक और नैतिक रास्तों के बजाय हिंसा में खोजने लगे हैं। किसी भी रिश्ते में मतभेद होना स्वाभाविक है। पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विचारों का टकराव हो सकता है। लेकिन किसी संबंध से बाहर निकलने के लिए कानून ने अनेक रास्ते दिए हैं। बातचीत, परामर्श, मध्यस्थता और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी अलगाव जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति हत्या जैसा कदम उठाता है, तो यह केवल अपराध नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध भी एक गंभीर हमला है।

इन घटनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू पारिवारिक संस्कारों और सामाजिक परिवेश से भी जुड़ा हुआ है। पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों को बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलता था। परिवार केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों की पाठशाला हुआ करता था। आज परिवार छोटे हो गए हैं और जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि माता-पिता के पास भी बच्चों के साथ बैठकर संवाद करने का समय कम होता जा रहा है। बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं, जहाँ उन्हें सही और गलत दोनों प्रकार की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में यदि परिवार मार्गदर्शन की भूमिका कमजोर कर दे, तो युवाओं के व्यक्तित्व और सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सोशल मीडिया और डिजिटल संस्कृति ने भी रिश्तों की प्रकृति को प्रभावित किया है। आज लोगों की अपेक्षाएँ अवास्तविक होती जा रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर दिखने वाले चमकदार जीवन को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर रिश्ता हमेशा रोमांच और खुशियों से भरा होना चाहिए। जबकि वास्तविक जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य, समझौता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। जब यह समझ विकसित नहीं होती, तब निराशा जन्म लेती है और कई बार यही निराशा विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। रिश्तों में बढ़ती हिंसा का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। आज तनाव, अवसाद, अकेलापन और असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। वे भीतर ही भीतर क्रोध, ईर्ष्या और हताशा को जमा करते रहते हैं। जब यह दबाव सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तब व्यक्ति आवेग में आकर ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम विनाशकारी होता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। यदि किसी व्यक्ति को अपने संबंधों में तनाव महसूस हो रहा है, तो उसे परिवार, मित्रों या विशेषज्ञों की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

इन घटनाओं से एक और गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या समाज में अपराध का भय कम हो रहा है? जब लगातार ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो लोगों के मन में यह चिंता स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है कि कहीं न कहीं कानून का डर कमजोर पड़ रहा है। अपराधियों को यह संदेश स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए कि चाहे अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, कानून के हाथ उनसे अधिक लंबे होते हैं। त्वरित और निष्पक्ष न्याय केवल पीड़ित परिवार को राहत नहीं देता, बल्कि पूरे समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करता है। यह भी सत्य है कि हर अपराध का दोष केवल किसी एक व्यक्ति पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। यदि परिवारों में संवाद कम हो रहा है, यदि युवाओं में सहनशीलता घट रही है, यदि नैतिक शिक्षा और मानवीय संवेदनाएँ कमजोर पड़ रही हैं, तो यह सामूहिक चिंता का विषय है। हमें यह समझना होगा कि स्वस्थ समाज केवल आर्थिक विकास से नहीं बनता, बल्कि मजबूत रिश्तों और मानवीय मूल्यों से बनता है।

पति-पत्नी के संबंधों में बढ़ती कटुता भी चिंताजनक है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। लेकिन आज कई बार इसे केवल व्यक्तिगत सुविधा और अपेक्षाओं के दायरे में सीमित कर दिया जाता है। जब अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं, तब संबंधों में दरार आने लगती है। ऐसे समय में संवाद, परामर्श और धैर्य की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से कई लोग इन रास्तों को छोड़कर टकराव और प्रतिशोध का मार्ग चुन लेते हैं, जिसका परिणाम अंततः दुख और विनाश के रूप में सामने आता है। इस तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि केतन अग्रवाल जैसे मामलों ने समाज को एक गहरी चेतावनी दी है। रिश्ते जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन जब उनमें विश्वास, संवेदना और सम्मान समाप्त हो जाता है, तब वही रिश्ते त्रासदी का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने परिवारों में संवाद को बढ़ावा दें, बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और किसी भी समस्या का समाधान कानून और विवेक के दायरे में खोजें। रिश्ते तोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी का जीवन छीन लेना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। एक सभ्य समाज की पहचान इसी में है कि वह मतभेदों को संवाद से सुलझाए और संबंधों को हिंसा नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम के सहारे मजबूत बनाए। तभी रिश्तों का यह अमूल्य ताना-बाना सुरक्षित रह सकेगा और समाज में मानवीय संवेदनाओं की रोशनी बनी रहेगी।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

'आपातकाल भारत के संविधान पर सीधा हमला था': कंगना रनौत

मुंबई/एजेन्सी

भारतीय इतिहास में 25 जून का दिन 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में जाना जाता है। इस दिन देश में 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जिसे लोकतंत्र और संविधान के हनन के रूप में देखा जाता है। इसी अवसर पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म 'इमरजेंसी' के निर्माण से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए कंगना रनौत ने फिल्म के पीछे की तैयारी, कलाकारों के अनुभव और फिल्म के कुछ सीन्स दिखाए हैं, जो आपातकाल के समय की कहानी को सामने लाते हैं। वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह उस दौर की घटनाओं को पर्दे पर उतारने के लिए मेहनत की गई। कंगना ने इस पोस्ट के साथ एक लंबा कैप्शन भी लिखा। अपने कैप्शन में उन्होंने कहा, ''आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे कठिन और अंधकारमय दौर में, यानी आपातकाल के समय, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। आपातकाल हमारे संविधान पर एक सीधा हमला था। इस दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुईं और लोकतंत्र की नींव मानी जाने वाली संस्थाओं पर भी गंभीर असर पड़ा।''

कंगना ने लिखा, ''मैंने इस विषय पर एक फिल्म का निर्देशन, अभिनय और निर्माण किया है। एक फिल्मकार के रूप में यह मेरे लिए एक बेहद असाधारण अनुभव रहा। आप सभी से अनुरोध है कि फिल्म 'इमरजेंसी' को नेटफ्लिक्स पर देखें।

आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल लागू करना ''केवल भारत के लोकतंत्र पर हमला नहीं था; यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधा हमला था।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए आपातकाल लगाने का पाप किया था। उन्होंने कहा, ''आज पूरा देश 25 जून 1975 का काला दिन याद कर रहा है, जब कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। सत्ता में बने रहने और अदालत के आदेश लागू न होने देने के लिए इंदिरा गांधी ने नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास किया। कांग्रेस का यह पाप लोकतंत्र और बाबा साहेब के सपनों पर सीधा प्रहार था। लालू प्रसाद व मुलायम सिंह यादव की वर्तमान पीढ़ी कांग्रेस का चाबुक भूलकर उसी के साये में राजनीति कर रही है।''मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को आपातकाल की 51वीं बरसी 'संविधान हत्या दिवस' पर लखनऊ में आयोजित 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के समर्थक राजनीतिक दलों, जनसामान्य व मीडिया से जुड़े सभी लोगों की आवाज को दबाया। उन्होंने कहा, ''ऐसा क्या था कि कांग्रेस को आपातकाल थोपना पड़ा, एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस ने सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह पाप किया और इस पाप को छिपाए रखने के लिए नौजवानों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं व सामाजिक संगठनों की आवाज को दबाने की चेष्टा की।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिए गए, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यही नहीं, रात के अंधेरे में भारत के संविधान की प्रस्तावना भी बदल दी गई। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिये बिना निशाना साधते हुए कहा, ''यह काम उसी कांग्रेस ने किया, जिसके युवराज आज संविधान की प्रति लेकर देशवासियों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र वर्तमान पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसीलिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' आयोजित करके पूरे देश व नौजवान पीढ़ी को इससे अवगत कराने का प्रयास हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के अत्याचार से आमजन व राजनीतिक दलों के नेता कराह रहे थे, लोकतंत्र के समर्थन में जेल जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ही नेताओं लालू प्रसाद व मुलायम सिंह यादव की वर्तमान पीढ़ी आज उसी कांग्रेस के साये में अपनी राजनीति करती दिखाई दे रही है।

कुंभाभिषेकम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को तमिलनाडु के कांचीपुरम में उपनिषद मठ और श्री राम यंत्र मंदिरम के प्रतिष्ठा समारोह (कुंभाभिषेकम) में शामिल हुईं।

'अगर आप नई दिल्ली में चुनाव लड़तीं तो लाखों वोटों से जीत जातीं': मेलोनी ने भारत यात्रा को याद किया

नई दिल्ली/भाषा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक नई पुस्तक में 2023 की अपनी भारत यात्रा का एक रोचक प्रसंग साझा करते हुए बताया है कि उनके स्वागत में नई दिल्ली की सड़कों पर उनकी मुस्कुराती तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए थे और यात्रा के बाद उन्हें धन्यवाद देने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे।

पत्रकार अलेस्सांद्रो साल्लुस्ती के साथ मेलोनी की बातचीत पर आधारित पुस्तक 'जॉर्जिया विजन' में मेलोनी ने कहा कि इन पोस्टरों को देखकर उनके साथ भारत यात्रा पर आए इटली के उपप्रधानमंत्री एंतोनियो तजानी ने मजाक में कहा था कि यदि वह नई दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें तो उन्हें ''10 लाख वोट'' मिल जाएंगे। मेलोनी ने मार्च 2023 की अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए कहा, ''जब मैं पहुंची, तो सड़क के किनारे हर कुछ दूरी पर मेरी तस्वीर और 'वेलकम' लिखा पोस्टर लगा हुआ था।

जब मैं वापस लौटी, तो मेरी तस्वीरों वाले पोस्टरों पर 'यात्रा के लिए धन्यवाद' लिखा हुआ था।'' इटली की प्रधानमंत्री ने कहा, ''मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी एंतोनियो तजानी ने मजाक में कहा, 'इतने सारे पोस्टरों के साथ यदि आप नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें, तो आपको दस लाख वोट मिल जाएंगे।'' मेलोनी ने 2023 में दो बार भारत का दौरा किया था। उन्होंने मार्च में 'रायसीना डायलॉग' के आठवें संस्करण में भाग लेने के लिए और सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा की थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ता प्यार से ''मेलोडी'' जोड़ी का हिस्सा कहते हैं। किताब के अध्याय 'हेड हेल्ड हाई अमंग द वर्ल्ड ग्रेट्स' में कहा गया है कि सफल कूटनीति के लिए अक्सर औपचारिकताओं की कठोर सीमाओं से आगे बढ़कर दूसरों से जुड़ने का ''अपना व्यक्तिगत तरीका'' खोजना पड़ता है।

'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री काजल अग्रवाल और अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने अपनी आगामी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के जरिए देश में बढ़ती खाद्य मिलावट (फूड अडल्टरेशन) की गंभीर समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक वीडियो संदेश साझा किया है। इस वीडियो में वे दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कह रहे हैं कि यह विषय हर भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ है।

ज़ी स्टूडियोज़ और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के सहयोग से प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण सागर बी. शिंदे ने किया है। हाल ही में जारी वीडियो में काजल और श्रेयस कह रहे है कि 'द इंडिया स्टोरी' केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को सामने लाने का प्रयास है, जो देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

फिल्म खाद्य मिलावट जैसी समस्या के छिपे हुए खतरों को उजागर करती है और आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का संदेश देती है। हालांकि निर्माताओं का भी मानना है कि मनोरंजन के साथ एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश प्रस्तुत करती यह फिल्म लोगों के बीच इस विषय पर चर्चा शुरू करने और जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज़ होगी।

फिल्म के सह-निर्माताओं में स्वाति विनायक सैंदाने, अनीता जाधव, विनायक सैंदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी शामिल हैं। तकनीकी टीम में निशांत भागवत (छायांकन), मंगेश ढाकडे (संगीत), आशीष म्हात्रे (संपादन), शकील आज़मी (गीत) और अनमोल भावे (साउंड डिज़ाइन) शामिल हैं। अपने दमदार विषय और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के साथ 'द इंडिया स्टोरी' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करने के साथ-साथ एक सशक्त सिनेमाई अनुभव भी देने का वादा करती है।

बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुंचीं उनकी ऑनस्क्रीन 'भाभी'

मुंबई/एजेन्सी

हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। अब इस कड़ी में 'बागी 3' में उनकी भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भी अपने पति विक्की जैन के साथ बागेश्वर बाबा से मिलने पहुंचीं। इस मुलाकात की तस्वीरें अंकिता और विक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें दोनों बागेश्वर बाबा के सामने बैठे हुए आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में तीनों एक साथ कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में अंकिता लोखंडे ने लिखा, कुछ मुलाकातें पहले से तय होती हैं और कुछ आशीर्वाद बहुत कीमती होते हैं। बागेश्वर धाम बाबा के साथ इस दिव्य पल के लिए हम आभारी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने भी बागेश्वर बाबा से मुलाकात की थी। इस दौरान समाजसेवा और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्हें बागेश्वर बाबा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनसेवा कार्यों की जानकारी दी गई। इनमें गरीब बेटियों के लिए प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का निर्माण और बागेश्वर धाम में चल रही मां अन्नपूर्णा प्रसादम रसोई भंडारे जैसी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। टाइगर श्रॉफ ने इन सभी कार्यों के बारे में ध्यान से सुना और खुले दिल से सराहना की।टाइगर श्रॉफ और अंकिता लोखंडे ने फिल्म 'बागी 3' में साथ काम किया था। इसी फिल्म में अंकिता ने उनकी ऑनस्क्रीन भाभी रुचि नंदन चतुर्वेदी का किरदार निभाया था, जबकि रितेश देशमुख उनके पति के किरदार में नजर आए थे। अगर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और शुरुआत में सिर्फ एक कॉमन दोस्ती थी। लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे।समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। साल 2019 में विक्की जैन ने बेहद रोमांटिक अंदाज में अंकिता को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। 2021 में दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों फिलहाल कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में नजर आ रहे है।

आम महोत्सव

बिहार के सहकारी मंत्री रामकृपाल यादव गुरुवार को पटना के कोऑपरेटिव भवन में नाबार्ड द्वारा आयोजित 'मैंगो फेस्टिवल' (आम महोत्सव) के दौरान।

बचपन में जिन सितारों को देखती थी, आज उनके साथ काम कर रही हूं : मोना सिंह

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अभिनेत्री मोना सिंह ने मेहनत और समर्पण के दम पर खास मुकाम बनाया है। इस कड़ी में मोना सिंह ने अपने सफल करियर का राज खोला है। उन्होंने बताया कि सफलता का सबसे बड़ा राज अपने काम से प्यार करना और कभी हार न मानना है। आईएएनएस से बात करते हुए मोना सिंह ने अपने करियर के सफर को याद किया और बताया, ''मैंने हमेशा एक बात पर भरोसा किया है कि अगर इंसान की नीयत सही हो और वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे, अपने हुनर को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करे, तो उसे काम जरूर मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं होती, बल्कि अनुशासन और मेहनत भी उतना ही जरूरी होता है। यही बातें मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही हैं।'' मोना ने कहा, ''मैं बचपन में जिन कलाकारों और फिल्मों को बड़े ध्यान से देखा करती थी, आज उन्हीं लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यह मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है। जब मैं उन कलाकारों से मिलती हूं, उनके साथ शूटिंग करती हूं और उनकी आवाज में अपना नाम सुनती हूं, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई है। मैंने अपने करियर में जो भी हासिल किया है, वह लगातार मेहनत और धैर्य का नतीजा है।''इन दिनों मोना सिंह कई बड़े और चर्चित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। हाल के समय में वह 'हैप्पी पटेल', 'बॉर्डर 2', 'कोहरा सीजन 2', 'सूबेदार' और 'मां का सम' जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आई थीं। अब जल्द ही वह राजकुमार हिरानी की डेब्यू सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' में भी दिखेंगी। इस सीरीज का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है। वहीं, अरशद वारसी, वीर हिरानी, इङ्कविक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और मोना सिंह अहम भूमिकाओं में हैं। कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर सीरीज 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

मीम्स और रील्स के दौर में कॉमेडी करना और अधिक चुनौतीपूर्ण : अक्षय कुमार

मुंबई/भाषा। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि लोगों को हंसाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यह काम और कठिन हो गया है, क्योंकि आज हर कोई मजेदार रील्स, मीम्स और स्टैंड-अप प्रस्तुतियों से रूबरू हो रहा है।

फिल्म 'भूत बंगला' के बाद अक्षय अब कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज की तैयारी में हैं। यह फिल्म 'वेलकम' फ्रेंचाइजी का हिस्सा है और शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

कम बोलो, सीधा कमाल करो : रचित सिंह

मुंबई/एजेन्सी

एक्टर रचित सिंह अपनी आने वाली फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें वो सिद्धू का किरदार निभाएंगे नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज से पहले रचित ने डायरेक्टर नचिकेत सामंत के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उनके शांत और सुकून भरे अंदाज ने सेट पर बिल्कुल नेचुरल माहौल बना दिया। रचित ने बताया कि नचिकेत का रिलैक्स वर्किंग स्टाइल एक्टर्स को पूरी तरह अपने किरदार में घुसने का मौका देता है, जिससे पूरी क्रिएटिव प्रोसेस काफी सहज और सहज लगती है। डायरेक्टर के साथ काम करने पर रचित बोले, नाची के साथ काम करना काफी रिलैक्स्ड था क्योंकि वो बहुत चिल और शांत हैं।

सेट पर चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैनिक नहीं करते, और उनकी यही एनर्जी एक्टर को ग्राउंडेड रहने और उस पल में प्रेजेंट रहने में मदद करती है। वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन एक-दो शब्द या छोटे पॉइंटर्स देकर सीन को समझते हैं, उसके स्टेक्स बढ़ाने और कैरेक्टर को बेहतर कैचिंग में मदद करते हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके लिए ज़्यादा तैयारी (झीशरिरिंळेप) नहीं रूह, बल्कि वो पल में जीने, सुनने, डायरेक्शन लेने और सीन को नेचुरल तरीकों से होने देने में विश्वास रखते हैं।

नचिकेत के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। 'बेबी डू डाई डू' में रचित सिद्धू का किरदार निभा रहे हैं, जो एक म्यूजिशियन और म्यूजिक टीचर हैदिल से अच्छा इंसान, जो अपने चाहने वालों के लिए हमेशा खड़ा रहता है।

यह किरदार उनके पिछले इंटेंस और डार्क कैरेक्टर वीरेन (फिल्म 'थम्मा') से बिल्कुल अलग है। सिद्धू के ज़रिए रचित इस बार अपने क्राफ्ट का एक सॉफ्ट और दिल छू लेने वाला साइड दिखाने वाले हैं। 'बेबी डू डाई डू' 3 जुलाई को रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

खुशाली कुमार ने 'दुल्हनिया ले आएगी' को बताया अपने करियर का खास किरदार

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री खुशाली कुमार अपनी आने वाली फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' को लेकर काफी चर्चा में है। फिल्म के फर्स्ट लुक से उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस कड़ी में उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए अपने लुक और किरदार के बारे में विस्तार से बताया। आईएएनएस संग बातचीत में खुशाली कुमार ने कहा, जैसे ही मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी, मुझे लगा कि यह किरदार मेरे लिए ही बना है। मेरा किरदार कोई साधारण दुल्हन नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। वह अपने फैसले खुद लेती है, अपने दिल की बात खुलकर कहती है और किसी भी बात को छुपाकर नहीं रखती। यह किरदार बहादुर भी है, भावनात्मक भी है और अपने अंदाज में जीने वाली है, और यही बात मुझे इस फिल्म की तरफ खींच लाई। उन्होंने कहा, ''फिल्म का जो फर्स्ट लुक सामने आया है, वह सिर्फ शुरुआत है और असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मेरे किरदार में कई परतें हैं, जिन्हें दर्शक फिल्म के साथ धीरे-धीरे समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस दुल्हन के अलग और अनोखे अंदाज को जरूर पसंद करेंगे।''

वहीं फिल्म के निर्देशक आकाशदित्य लामा ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा, '''दुल्हनिया ले आएगी' एक ऐसी कहानी है जो परिवार, रिश्तों और उनके बीच की उलझनों को मजेदार अंदाज में दिखाती है। आज के समय में रिश्तों की जटिलताएं बढ़ गई हैं, और इस फिल्म में उन्हीं भावनाओं को एक मनोरंजक रूप में पेश किया गया है।''निर्देशक ने कहा, ''फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका मुख्य किरदार है, यानी दुल्हन। यह दुल्हन पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। उसमें आत्मविश्वास है, थोड़ी शरारत है और वह कई बार दर्शकों को चौंका भी देती है। यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों को जोड़ने की क्षमता रखती है क्योंकि इसमें हंसी, भावनाएं और परिवार का मेल है।''फिल्म के पहले पोस्टर की बात करें तो उसमें खुशाली कुमार दुल्हन के अवतार में नजर आ रही हैं। उन्होंने ब्राइडल लहंगा पहना हुआ है, लेकिन उसके साथ सनग्लासेस लगाए हुए हैं। यह कॉम्बिनेशन ही फिल्म के किरदार की खासियत को दर्शाता है कि यह दुल्हन साधारण नहीं है, बल्कि अपने अंदाज में जीने वाली लड़की है। यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मन, शरीर और आत्मा के समग्र विकास हेतु ईवॉल्व का हुआ आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) साउथ लेडीज़ विंग द्वारा केकेजी ज़ोन के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय मेगा इवेंट 'ईवॉल्व' का आयोजन मंगलवार को हुआ। केकेजी ज़ोन के मुख्य सचिव दिलीप जैन एवं कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके साथ ही बेंगलूरु नॉर्थ, शिवमोग्गा, बेलगावी, बीजापुर, दावणगेरे, गदग एवं हुब्बल्ली सहित विभिन्न चैप्टर्स से बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्याएं शामिल हुईं। साउथ की चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने कहा कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने, सीखने और स्वयं को विकसित करने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि ईवॉल्व, केवल दो दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वयं के बेहतर स्वरूप की खोज का अवसर है। केकेजी ज़ोन लेडीज़ विंग की संयोजिका पिंकी जैन, सहसंयोजिका कीर्ति जैन, बिंदु रायसोनी, ओमप्रकाश जैन, दिलीप जैन अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर विभिन्न चैप्टर्स से आई पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए अनुभव साझा किए।

कविता मूथा एवं संगीता सियाल ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ईवॉल्व का उद्देश्य प्रत्येक महिला को स्वयं के लिए समय देना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना तथा आत्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध करना है। मुख्य सचिव निधि पालरेचा ने संचालन किया। लेडीज विंग की टीम ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इस आयोजन में प्रतिभागियों के लिए विभिन्न उपयोगी सत्र आयोजित किए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बाबा का विशेष श्रृंगार

ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर गुरुवार को बन्नरघट्टा रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पर बाबा श्याम की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया तथा विशेष सजावट की गई। सुबह से ही मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कतारबद्ध होकर भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। सायं 4.15 बजे से मंदिर परिसर में भजनों का कार्यक्रम हुआ जिसमें स्थानीय गायकों ने भक्ति रसधारा से श्रद्धा व आस्था का समा बांध दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्याम भक्त उपस्थित थे।

सोलस-2 कामपलेक्स जिनालय का अंजनशलाका प्रतिष्ठा महोत्सव 3 जुलाई से

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के शंखेश्वर पार्श्वनाथ ट्रस्ट द्वारा निर्मित नूतन जिनालय की अंजनशलाका प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त गच्छाधिपति जैनाचार्य युगभूषणसूरीजी (पंडित महाराज साहब) द्वारा प्रदान किया गया। ट्रस्ट के ट्रस्टी कुशलराज गुलेच्छा ने बताया कि शहर के जेसी रोड के सोलस-2 काम्पलेक्स में स्थित जिनालय की अंजनशलाका का मुहूर्त 3 जुलाई और प्रतिष्ठा का मुहूर्त 4 जुलाई का प्रदान किया गया है। सोलस काम्पलेक्स के किशोर जैन ने बताया कि अंजनशलाका प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित महाराज और आचार्यश्री अरिहंत सागरजी अपनी निश्रा प्रदान करेंगे। अशोक नागोरी ने बताया कि मन्दिर में प्रतिष्ठित होने वाले शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा की घड़ाई का काम संतश्री कुशलकीर्तिसागरजी के मार्गदर्शन में अहमदाबाद और जयपुर में विधिपूर्वक चल रहा है। महावीर मेहता ने बताया कि परिकर का कार्य सूरत में माधवभाई के मार्गदर्शन में तथा शिल्पकला का कार्य चेतन सोमपुरा द्वारा किया जा रहा है। प्रवक्ता ललित डाकलिया ने बताया कि संतों से मुहूर्त निवेदन के समय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट के ट्रस्टी राजू सुजानी, नेमीचंद रांका, राजू हिरानी के साथ ट्रस्ट मंडल के अनेक ट्रस्टी उपस्थित थे।

'ग्रूमिंग मंत्रा 2.0' की कार्यशाला में जीतो महिलाओं ने सीखी मेकअप की बारीकियां

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन(जीतो) नार्थ लेडीज़ विंग द्वारा बुधवार को राजाजीनगर कार्यालय में ग्रूमिंग मंत्रा 2.0-मेकअप प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। संयोजिका नेहा भंडारी ने कार्यक्रम की जानकारी दी। नॉर्थ की अध्यक्ष लक्ष्मी बाफना ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंत्री रक्षा छाजेड़ ने की। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा निरंतर सीखने की भावना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सीखो और आत्मनिर्भर बनो। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मेकअप विशेषज्ञ सोनम जैन द्वारा संचालित प्रशिक्षण सत्र रहा। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से त्वचा की तैयारी, मेकअप तकनीकों तथा पेशेवर सुझावों एवं उपयोगी उपायों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं को ग्रूमिंग, त्वचा की तैयारी तथा मेकअप की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सम्मान

बेंगलूरु के पुष्कर जैन आराधना भवन में बुधवार को अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ बेंगलूरु के सदस्यों द्वारा आचार्यश्री पार्श्वचंद्रजी व डॉ. पद्मचंद्रजी के दीक्षा दिवस पर संतों की निश्रा में अतिथि के रूप में उपस्थित शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील शर्मा का सम्मान किया गया। शर्मा ने आचार्य, संतों एवं मुनिवृन्दों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

अवलोकन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

साध्वीश्री पावनप्रभाजी आदि ने गुरुवार को श्रीरामपुरम में तेरापंथ युवक परिषद, राजाजीनगर द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर, डेंटल केयर एवं डे-केयर सेन्टर का दौरा किया। तेयुप राजाजीनगर के अध्यक्ष राजेश देरासरिया ने श्रीरामपुरम सेन्टर के तीन तलों में उपलब्ध विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर राजाजीनगर सभा, तेयुप गांधीनगर के अध्यक्ष विनोद कोठारी एवं अन्य पदाधिकारियों सहित कुल 25 सदस्य उपस्थित थे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं पर उस्तरे से हमला करने के आरोप बेबुनियाद : चेन्निथला

कोच्चि/भाषा। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में सचिवालय तक निकाले गये विरोध मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एसएफआई कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए उस्तरे का इस्तेमाल किये जाने के आरोपों को बृहस्पतिवार को सिरे से खारिज कर दिया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विभिन्न कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की फीस बढ़ा दी है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान एसएफआई के कई कार्यकर्ता घायल हो गए।संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उस्तरे का इस्तेमाल किया।कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ये उस्तरे अवरोधक लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियों को काटने के लिए लाए गए थे।

चेन्निथला ने यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आरोपों को खारिज किया और कहा कि इस बात की जांच के आदेश दिए गए हैं कि उस्तरे कौन लाया था, जिनका इस्तेमाल जाहिर तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए किया जाना था। उन्होंने कहा, जब पुलिसकर्मियों के पास लाठियां होती हैं, तो उनके लिए ब्लेड का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। हम जांच करेंगे कि ब्लेड कौन लाया था। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि उस्तरा लाने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

चेन्निथला ने कहा कि वह भी छात्र राजनीति से ही आए हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कभी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा, ''सैकड़ों उस्तरे लाए गए थे और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो ब्लेड लाए थे और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।''माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उस्तरे का इस्तेमाल कर एसएफआई कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

संसार से पार उतरने के लिए आराधना व साधना जरूरी : डॉ समकितमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के शूले जैन स्थानक भवन में विराजित श्रमण संघीय आचार्यश्री शिवमुनिजी के आज्ञानुवर्ती डॉ समकितमुनिजी ने प्रवचन देते हुए कहा कि जैन दर्शन में एक मौलिक शब्द है - परित। जो साधक संसार सागर से पार उतर जाता है उसे परित कहते हैं। संसार समुद्र से पार जाने के लिए साधक को आराधना और साधना करनी जरूरी होती है। इस प्रसंग पर समकित मुनि ने दृष्टांत सुनाया। प्रवचन सभा में शूले के अलावा सिंधनूर, आम्बूर व आसपास के अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। इस प्रसंग पर शूले संघ के अध्यक्ष उत्तमचंद कोठारी, महामंत्री सुनील

कुमार मरलेचा सहित रत्न हितैषी श्रावक संघ, सुधर्म ज्ञानगच्छ श्रावक संघ, शांत क्रांति संघ, केवल मुनि जैनोदय ट्रस्ट, जैन कान्फ्रेंस, शूले कल्याण मित्र मंडल, रत्न हितैषी युवक मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित थे।

प्रमाद में समाप्त हो जाती हैं अच्छी संभावनाएं : आचार्य विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायचूर। शहर के पास शक्तिनगर स्थित थर्मल पॉवर स्टेशन परिसर में विविध क्षेत्रों के अधिकारियों और श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए जैनाचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि सबको मौत आनी है। यहां का कमाया सब यहीं छूट जाने वाला है। सिर्फ धर्म की साधना और आत्मगुणों का किया हुआ विकास ही हमारे काम आता है। आज तक के इतिहास में लाखों-करोड़ों धनकुबेर इस दुनिया से चले गए और बड़ी-बड़ी सल्तनतें स्वाहा हो गई। कोई अपने साथ कुछ भी लेकर न जा सका। दूसरी ओर जिन्होंने समय का सदुपयोग कर आत्मतत्व की साधना की, उन्होंने बहुत-कुछ पाया और वे दुनिया को बहुत-कुछ देकर गए। ऐसे साधकों का जीवन सबके कल्याण का कारक बना। प्रमाद में तो व्यक्ति स्वयं का दूसरों का, किसी का कल्याण नहीं कर पाता, इसलिए प्रमाद अल्प मृत्यु है यानी जीतेजी मरा हुआ।ङ्गआचार्यश्री ने कहा कि प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमाद के वशीभूत जीवन की अनेक उजली संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। भगवान महावीरस्वामी ने प्रमाद को मृत्यु के तुल्य कहा है। जीवन का अमूल्य समय मात्र भौतिक उपलब्धियों के लिये ही नहीं है, मानवीय जीवनमूल्यों के जतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिये भी समय व शक्ति लगनी चाहिए। प्रमादी मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों की संभावनाएं गंवा देता हैं। जीवन के समुचित विकास के लिए प्रमाद रहित बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। सिर्फ हाथ पर हाथ देकर बैठे रहने अथवा प्रतीक्षाओं और सपनों में जीवन पूरा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, जीवन व्यर्थ हो जाता है। भगवान महावीर ने तो स्पष्ट कहा है कि अपने और कुटुंब-काबिले के लिए भौतिक सामग्री का संपादन करना ही जीवन का वास्तविक ध्येय नहीं है, मनुष्य जीवन की सफलता तो चेतन के चरम विकास और उसकी पवित्रता में है। आध्यात्मिक उन्नति ही मनुष्य जीवन मकसद बनना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निर्जला एकादशी के अवसर पर काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के जलाभिषेक के लिए राजेंद्र प्रसाद घाट से आयोजित 'कलश शोभा यात्रा' में भाग लेते श्रद्धालु।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मुलाकात

अणुव्रत विश्व भारती सोसायटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को बेंगलूरु के लोकभवन में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचन्द गहलोत से शिष्टाचार भेंट कर अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट-2026 की अवधारणा, उद्देश्यों एवं राष्ट्रव्यापी नैतिक जागरण अभियान की जानकारी प्रस्तुत की। इस प्रतिनिधिमंडल में सोसायटी की उपाध्यक्ष डॉ. कुसुम लूनिया, संगठन सचिव राजेश चावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

महादेवपुरा गौशाला में शांतिनाथ गौभक्त मण्डल ने की गौसेवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के शांतिनाथ गो भक्त मण्डल के सदस्यों ने गुरुवार को निर्जला एकादशी के मौके पर महादेवपुरा गौशाला में विशेष गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर गायों को हरा घास दिया। मण्डल के पदाधिकारियों, सदस्यों ने गौशाला में पहुंचकर गौमाताओं को अपने हाथों से चारा खिलाया तथा उनकी सेवा की। मण्डल के अध्यक्ष नारायणसिंह सुराणा, उपाध्यक्ष श्यामलाल पटेल, दीपाराम मोकनी व अन्य सदस्यों ने गौशाला की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**